पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

www.samaymaya.com

पंजीयन क्रमांक RNI-MP\HIN\2006/20685

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/march09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com
(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 4 अंक 43 | इंदौर, सोमवार 24 मई से 30 मई 2010 तक | पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 एम.पी. जीतकर, बर्बाद कर रहा एम.पी.

3 भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्ट जालसाज शीर्ष पद पर

4 कल सबको मिले जल आज हो व्यवस्था

5 उज्जैन की अंदेक्षण रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की बातगी

6 अपनी लूट के लिए सबको खुली छूट

7 इंदौर-उज्जैन ४ लेन में भ्रष्टाचार का तांडव

संयुक्त राष्ट्रसंघ बनाम विश्व का संयुक्त शैतान संघ

विश्व पर अमेरिकी साम्राज्य स्थापित करना है मूल उद्देश्य

विश्व के सभी मानवों की संकर प्रजाति, महाधूर्त, महाचालाक पर महामूर्ख

पृथ्वी के संचालन में प्रकृति के अपने प्राकृतिक नियम है पृथ्वी की प्रकृति के सभी प्राणियों में मानव नाम का प्राणी उसकी सर्वोत्तम कृति है। पृथ्वी की प्राकृतिक क्रियाओं को चलाने के लिए उसके अपने नियम और सिद्धांत हैं। उसने सभी को संतुलित करने और रखने के लिए हर पल और उसकी क्रिया को एक दूसरे से कहीं अत्याधिक अदृष्य सूक्ष्म रूप से जोड़ा है। तो कहीं दृश्य विशाल रूप से जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होने के बाद भी अपनी बुद्धि जागृत होने के बाद भी मानव स्वीकारता नहीं तो मात्र तात्कालिक लाभ और स्वार्थ के कारण।

भारत भूमि पर इतिहासों में वर्णित पुराणों के अनुसार वर्तमान स्वरूप में साधारण मानव रूप में विद्यमान दानवों से बढ़कर विशाल शक्तिशाली दैत्याकार दानवों से लेकर उनके दमन के लिए बहुविधि रूपी देवों, जिनमें कृष्ण से लेकर नृसिंह अवतार बजरंगबली का भी वर्णन मिलता है, अगर दानवों ने सभी प्राणियों के साथ मानवों का शोषण और दमन किया तो राम, कृष्ण, जैसे देवों नेप्रकृति के सभी प्राणियों, मानवों की रक्षा करते हुए दानवों से बचाया। वर्तमान में भी भ्रष्ट दानवों का भी जो है तो साधारण मानव परंतु अपने स्वार्थों के लिए प्राकृति

उसके आंगन में निवास करने वाले अन्य जीवों के साथ मानवों का भी शोषण और दमन करने में लगे हैं। साथ ही विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए बहुविध तरीकों से न केवल प्रकृति के प्राणियों, वनस्पतियों को नष्ट करने, नस्लें बिगाड़ने, विषैला बनाने, गुण धर्मों में परिवर्तन कर उसकी मूल गुण धर्मिता नष्ट करने पर ही तुले हैं। हमारे राष्ट्र के सत्ताधीश तत्कालिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे नीच दानवों का अनुसरण कर अपनी गुलाम मानसिकता के चलते ऐसे दुष्टों के सामने सिर झुका स्वीकार कर न केवल मानवों, प्रकृति के अन्य जीवों, साथ ही पूरी प्रकृति को नष्ट करने पर तुले हैं। दानवीयता के इस विकराल रूप का भारतीय पुराणों और धर्मशास्त्रों में भी कहीं वर्णन नहीं मिलता। दानवों की इस विनाशलीला का भले ही मानव प्रतिरोध, प्रतिकार न कर सके, इसके विपरीत प्रकृति अपने तरीके से इन दानवों का समूल नष्ट कर देगी।

पाठक समझ चुके होंगे कि हमारा मंतव्य अमेरिका की इस दानव लीला से है जो समझदार और सक्षम थे उन्हें अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की संस्था बनाकर अपना संयुक्त शैतान संघ बना लिया, अमेरिका का पूरा देश दुनिया के ऊपर गुंडागर्दी कर पोश तरीके और नियम कानून बनाकर उस देश की सरकारों के मुखियाओं को भ्रष्टाचार का टुकड़ा डाल एटीबी, विश्वबैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन बांटकर अपना पालतू श्वान बनाकर अपने हिसाब से नचाता है।

संयुक्त शैतान संघ- युनाइटेड नोटोरियस आर्गेनाइजेशन-

अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए आतंकवादियोंको सहयोग करना, जैसा कि 1980-90 से तालिबानियों को सहयोग कर रूस में चीन, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अपने हथियार बेचे।

फ्रूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन

असली उद्देश्य-अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दवाओं को बेचकर सैकड़ों राष्ट्रों का बर्बाद किया, मेक्सिकों जैसे राष्ट्रों की पूरी कृषि व्यवस्था ही हरामखोरों ने चौपट कर डाली। भारत में भी यही षड़्यंत्र चल रहा है यूनियन कार्बाइड 2 दिसम्बर 1984 भोपाल गैस त्रासदी इन्हीं धूर्तों का भयावह परिणाम थी, भारत में लाखों किसानों ने 1990 से अभी तक पूरे भारत में आत्महत्याएं की। इन्हीं श्वानों की जालसाजी है बीटीजीएम फसलें रासायनिक खाद, कीटनाशक ये ही पूरी दुनिया का पर्यावरण चक्र बिगाड़ रहे हैं।

भारत में कारिस्तानी

पूरी दुनिया मेंफूड सेफ्टी के नाम इसने पूरी दुनिया में अपनी कंपनियों का उन देशों की कृषि फसलों पर कब करने वहां के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर भिखारी बनाने का कानून के माध्यम से जाल बिछा दिया, भारत के मुखैर कांग्रेसियों ने भी इसके लिए कई कानून बना दिए हैं। (शेष पेज 2 पर)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. २००६

पूरे राष्ट्र को नक्सलाईट बनाने की तैयारी

नेताओं, पूंजीपतियों, अधिकारियों के शोषण का परिणाम है, नक्सलबाद

समय माया ने खाद्य एवं मानक अधि.खंड की पिछले कई अंकों में लगातार प्रकाशित कर केन्द्र के धुर्तों जिसमें सड़ते हुए महानीच खान शरद पंवार, कृषि मंत्री भारत शासन महाजालसा चीट अंवर, मनमोहन जो रिलायंस और आईटीसी की कठपुतली बन राष्ट्र की जनता को कदम कमद नोचतें रहे है। और भविष्य में पूरा राष्ट्र का खाद्य उद्योग भाग मोटे कमीशन के लिए उनके हवाले करने पर तुले हुए है। वास्तविकता में २ से ५ करोड़ लोगों को बेरोजगार कर पूरे राष्ट्र के अभी भाग १० राज्यों में फैला देने का दुष्क्रम कर रहे है।

हाल ही में ७६ सीआरपीएफ के जवानों की हत्या से गृहमंत्री चीर अंबर जो पेशे से वकील हे ओर टाटा, रियालंस जिंदल हिंडाल को, जैसी अनेकों राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कं. को, छत्तीसगढ़, अधिकांश खनिजों, कोयलों, तांबा, लोहा, क्रोमोजाइट किंवर लाइट जैसे कीमती अयस्कों को धरती से निकालने के लिए केन्द्र और छत्तीसगढ़ राज्य की भाजपा सरकार के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके है।यह वही जमीने है, जिनका मालिकाना हक आदिवासियों का है, उन्हें दमन, डरा-धमकाकर जमीनें हथियानेके साथ उन आदिवासियों से कृषि का मूल अधिकार छीनने पर भी आमदा है। दूसरी और चाहे शासन भाजपा का हो या कांग्रेस का, अधिकारी आईएएस, एसएएस जो महाराष्ट्र और कदम-कदम पर नोंच खसोंट के आदि हो चके है। तो भी पूंजीपतियों और नेताओं के इशारे पर इन आदिवासियों का हर कदम शोषण करते हैं। आखिर वो आदिवासी एक तरफ कृषि भूमि से परेशान हे, तो दूसरी तरफ इस टिकडी के अत्याचारों और भ्रष्टाचार से , स्वाभाविक है, वह विद्रोह करेगा, जिसके लिए नक्सलाइट और माओवादी सबसे सटीक मंच होता है, बेशक वर्तमान में उसे चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान से नेपाल के माध्यम से तो हथियार मिलते ही है, तो दूसरी तरफ चो भाजपा हो या कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थपूति के लिए भी इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग करते है। दूसरी तरफ चूंकि अब नक्सली और माओवादी संगाठित गिरोह है, तो वह भी आंध्र प्रदेश,झारखंड, उडीसा, कर्नाटक, बिहार छत्तीसगढ़ में भी जान धमकी की देकर न व्यापारियों, पूंजीपतियों, ठेकेदारों, बहुराष्ट्रीय, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों से भी महिना और हफ्ता वसूली करता है, जिसका दस राज्यों में रु. १५ से २० हजार करोड़ वार्षिक का लेन-देन है। जिससे वो अपने सदस्यों को वेतन, देने से लेकर हथियार खरीदने तक का कार्य करते है।

(शेष पृष्ठ २ पर)

संपत्ति घोषणा की नौटंकी- मंत्री, आईएएस, आईपी एस, आईएफएस

९९ प्रतिशत झूठी और जालसाजी पूर्ण जानकारी

स्वयं की नहीं, रिश्तेदारों के नाम से, देश विदेश में अरबों रु

राष्ट्र की राजधानी के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से लेकर संसद सभी शासकीय विभागों में बैठे मंत्रियों, न्यायाधीशों, इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारियों इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन सर्विस, इंडियन रेवेन्यु (ईटिंग) सर्विस, इंडियन फारेस्ट(ईटिंग) सर्विसेस, इंजिनियर्स, डाक्टर्स आदि ८० प्रतिशत अरबपति, खरबपति है १९ प्रतिशत ५ से ९९ करोड़ के मालिक, १ प्रतिशत मुश्किल से ही रु. १ करोड़ से कम के मालिक होंगे, जिन्होंने जो घोषणाएं की है, वो कागजी आंकड़ों के स्तर पर जो भी है, इसके विपरीत १९ प्रतिशत मक्कारों और धूर्तो की फौज ने वास्तविक्ता से सारी जानकारियां झूठी और जालसाजी पूर्ण की है। वैसे भी ९९ प्रतिशत का पैसा ही है, जो इनके नाम से न भी हो, तो भी गांवों से लेकर नगरों, शहरों, महानगरों तक जो चमक शपिंग माल्स, फैक्ट्रियों, बड़ी कंपनियों, कालोनियों, चाय-पान की दुकानों की तरह खुलने वाले इंजिनियरिंग, फार्मो, प्रबंधन कंप्यूटर साइंस, मेडिकल कालेजो, स्कूलों तक में लगने वाला सारा पैसा काला धन ही है। जो यहां तक कि राष्ट्र के शेयर बाजारों में लगा ७० प्रतिशत देशी विदेशी धन भी काला धन ही है, जिसका परिणाम ही है शेयर बाजार १७००० के आस-पास घूम रहा है। शेयर बाजार से कुल काला धन भारत से अवैध तरीके से पहुंचाया विदेशों में फिर विदेशों से विदेशी धन के रुप में लौटा वही धन ही लगा हुआ है, इसे हटा दीजिए तो भारतीय शेयर बाजार ३ से ४००० के बीच आ जाएगी।

स्कूलों, कालेजों की फीस ५ से १० प्रतिशत पर आ जाएगी। बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें ५० से ६० प्रतिशत गिर जाएंगी। कांग्रेसी गिरोह के डकैतों का उद्देश्य कदापि महंगाई रोकना, काले धन की बाढ़ को रोकने की अपेक्षा काले धन की बढ़त, महंगाई बढ़ाने जनता को लूटने में ही सारी उर्जा व्यय की जाती है। लाख विपक्ष चिल्लाए महंगाई कम करने की बात और मुद्दे उछाले तो रु.४०० करोड़ की राहत की घोषणा तो करेंगे पर वास्तविक प्रयास कदापि नहीं, गुलाम सरदार मनमोहन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि खाद्य वस्तुओं पर सट्टा और वायदा व्यापार पर, जो महंगाई का मूल कारण है, और कालेधन को जो भ्रष्टाचार, सफेद पोस डकैती से कमाया गया है। वायदा व्यापार के जरिए आसानी से सफेद कर मूल व्यवसाय की आधार भूत पंजी के रुप में उपयोग किया जा रहा है। मूलतः महंगाई बढ़ाने जो खाद्य वस्तुओं, भूमि भवन उद्योगों तक की कीमतों में भारी हजारों गुना उछाल का कारण है।

वास्तविकता में केन्द्र में बैठे कांग्रेसी सत्ताधीश डकैतों का उद्देश्य कालाधन कमाना बढ़ाना और जनता को नोंचना हे, स्वाभाविक सत्ताधीशों के पास अरबों से लेकर सैंकड़ों खरब का धन तो है, उस धन को निवेश करने के लिए कानूनी दांव पेचो की भी व्यवस्था है, अपने नाम से नहीं रिश्तेदारों के नाम पर देश, विदेश में विनियोजित करने की। इन सब तथ्यों के विपरीत सबसे मजेदार यह है कि संपत्ति की घोषणा से जनता ने न केवल इनके कदम-कदम झूठे जालसाजी और मक्कारी, शासकीय स्तर पर देखी और सामने आई, साथ ही जिन रिश्तेदारों के नाम से वह संपत्ति है, उन्हें आसानी से डकारने, दूसरा घोषणा के विपरीत अधिक संपत्ति होने पर आसानी से आरोपी अपराधी सिद्ध किया जा सकेगा, इनकी पद की महानता और श्रेष्ठता को तत्काल आईना दिखाकर निलंबित, सेवा समाप्त की जा सकेगी।

सम्पादकीय

लोकतंत्र नहीं कमीशन तंत्र

भारत विश्व का अनादिकाल से महाज्ञानियों का राष्ट्र रहा है।, इसके विपरीत यह राष्ट्रजो विश्व को प्रकाश स्तंभ की भांति अपने ज्ञान विज्ञान से अनादि काल से ही धरती के लालों की घोर स्वार्थी मानसिकता के चलते हजारों साल से गुलामी का दंश भी झेलता रहा।

वर्तमान में इस महाज्ञानियों,ध्यानियों राष्ट्र में लोक तंत्र चल रहा है, वह भी घोर स्वार्थी मानसिकता के चलते पूरा दलाली या कमीशन तंत्र बन चुका है। राष्ट्र के प्रधान मंत्री कार्यालय से चलकर गांवों की पंचायत के सरपंचों और सचिवों तक हर स्थान पर सत्ताधीशों को कमीशन दीजिए और हर वैध-अवैध अपने हित का और जन विरोधी राष्ट्र विरोधी काम करवा लीजिए भाड़ में जाने दीजिए वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के हितों को, राष्ट्र,पूर्व में भी विदेशियों और आकांओं का शिकार इसी घोर स्वार्थी मानसिकता के कारण हुआ था और वर्तमान में इसी का शिकार हो रहा है, इन धूर्त सत्ताधीशों, नौकरशाहों को कमीशन दीजिए, भारत की धरती में, इस राष्ट्रवासियों के वर्तमान और भविष्य से पूरा खिलवाड़ कीजिए, यहां की फसलों गेंहू, दाल, चावल, हल्दी, नीम, कपास,सब्जियों, फलों की मूल प्रजातिया का अमेरिका में अपना पेटेंट करना लीजिए बाद में उन्हीं पर फिर रॉयल्टी दीजिए और फसलों से लेकर औषधियों, योग, ज्ञान,विज्ञान तक पर हमारे ही मौकरशह, सत्ताधीश कमीशन डकार कर जनता को लुटवाने तैयार रहते है।यहां की जनता तो इन पर कमीशन नहीं देगी।पर वहीं माल जब विदेशों से आकर भारत में बिकेगा तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनिया इन भुखेरे को कमीशन का टुकड़ा डालकर जनता को नोचेंगे खसोंटेगें। बेशक यह कमीशन खोरी की कहानी का परमाणु भी नहीं है जिसे इन चंद शब्दों में व्यक्त किया जा सके। घोर स्वार्थी मानसिकता जागती है, ते आत्मस्वाभिमान संवेदनाहीन हो, शून्य हो जाता है। दलाली, कमीशन खोरी,रिश्वत या वृहद स्तर पर भ्रष्टाचार कुलांचे मारने लगता है फिर महत्वाकांक्षाएं दिवास्वप्नों को मूर्त रुप देने में जूट जाती है स्वहित के आगे जनहित, राष्ट्रहित धुमिल हो जाते है। यह इस धरती का ही नहीं वरन विश्व के सभी लोकतंत्रों का अभिषाप है।

भारत की श्रेष्ठ उर्वरा भूमि, यहां के मानवों में आत्म स्वाभिमान के भाव को, घोर स्वार्थी मानसिकता के आगे बौना बना देती हे, शायद ये इस धरती के गुणों की श्रेष्ठता में एक विपरीत दुर्गुण भी है। इस दुर्गुण को दूर करने के लिए ही, इस धरती पर ही विश्व के श्रेष्ठ महामानव कृष्ण, पुरुषोत्तम राम, जितेन्द्रिय महावीर के अवतार भी हुए, इसके विपरित हमारा स्वाभिमान, जनहित राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रेम तब से अभी तक स्थिर और जागृत न रह सका, फिर सत्ताधीश बन जाने के बाद तो महा षड्यंत्रकारी महाकमीशन खोर बन स्वहित साधन में, जनहित, राष्ट्रहित सौदेबाजी का आधार बन गया , यह आंतरिक और बाहरी सभी स्तर पर सभी शासकीय प्रशासकीय तंत्र जड़ों में छा गया अब वर्तमान परिदृष्य यह है, कि यहां ईमानदारों को मुंह छुपा कर जीवन यापन करना होता है, अब श्रेष्ठता में कौन कितनाबड़ा कमीशन खोर, भ्रष्ट है, वह उतना महान और श्रेष्ठ है। वह लोकतंत्र का श्रेष्ठ नेता होता है।अब ईमानदार, आत्म स्वाभिमानियों की जरूरत न तो घर में, न समाज में, न राष्ट्र में है। अब मूल्यांकन का पैमाना ज्ञान ईमानदारी नहीं, छल कपट, कमीशन खोरी से व बेइमानी से कमाए धन श्रेष्ठता का पैमाना है।

केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री धूर्त कमलनाथ

एम.पी. जीतकर, बर्बाद कर रहा एम.पी.

सभी रा.रा.पर होगी वसूली, लुटने क्यों आए म.प्र. में

केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमलनाथ म.प्र. में 1977 से एम.पी. अर्थात सांसद का चुनावजीत रहा है। दूसरी तरफ चूंकि म.प्र. से चुनावजीत रहा है,इसलिए म.प्र. को बर्बाद करने मे भी कोई कसर नही छोड रहा है। इसका एक प्रत्यक्ष तात्कालीन उदाहरण है। जिस जन 10 में उत्ताधूर्त जालसाज डकेत मंत्री ने घोषणा की थी कि म.प्र. मे रु 25000 करोड खर्च कर सारे राष्ट्रीय राजमार्गो को 4 ले न बनाया जाएगा उस घोषणा की वास्तविकता यह भी थी कि रु25000 करोड़ के बीओटी ठेकेदारो को पूरे प्रदेश के लगभग 3000 कि.मी. से ज्यादा मे राष्ट्रीय राजमार्गो को सौपकर वसूली की व्यवस्था करवाई जाएगी।

यहां पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है,कि म.प्र. में 1. पेट्रोल और डीजल पर केन्द्र सरकार का 32 प्रतिशत कस्टम एवासाइज के साथ 27 सडक, 27 शिक्षा, फिर म.प्र. सरकार की 32 प्रतिशत वाणिज्य कर 17 निगमों पालिकाओ के कर राष्ट्रीय राजमार्ग के हर मार्ग हर कि.मी. रु. 1 से 5 तक का अतिरित सड़क पर चलने का शुल्क लगेगा तो कोई भी बस,ट्रक, कार व अन्य वाहन चालक जिसे दूसरे प्रांत में जाना हैं, क्यों घूसेगा इस सरकारी डकैतीका शिकार बनने के लिए बंबाई से दिल्ली, कलकत्ता, आने जाने वाले ट्रक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र होकर जाएगें इससे दोनों तरफ नुकसान होगा, पेट्रोल डीजल तो नहीं बिकेगा साथ ही ठाबों होटलों व अन्य दुकानदारों का व्यवसाय को भी नुकसान होगा। पेट्रोल-डीजल, गैस की म.प्र. में अधिक कीमते होने के कारण पेट्रोल डीजल के आत्याधिक मिटटी तेल की मिलावाट को किलो के स्थान पर लीटर सक नापनें, वायुमंडलीय गैसे मिला देने के कारण अधिकांश वाहन चालक, पड़ोसी राज्यों से ही गैस, पेट्रोल डीजल भरवा कर ही घुसते हैं म.प्र. में अब जब सभी राष्ट्रीय और राज्य के मार्गों पर टोल वसूली होगी तो स्वाभिक हैं अधिकांश थोड़ा समय और ईधन ज्यादा खर्च कर वास्तविक टोल और ईंजन की कीमतें बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों से गुजरे से इससे कुल मिलाकर न केवल शासन को .. . सभी प्रकार के व्यापार को घाटा होगा। ये है रु. 25000 करोड़ खर्च करने की वास्तविकता और म.प्र. को कमल नाथको एमपी बनाने का उपहार दूसरी 5316 कि.मी. राष्टीय राजमार्ग में से 25000 कि.मी. से ज्यादा सड़के ज्यादा कमाई में और लूट ... लिए कांग्रेस और भाजपा को मोश धन देने व लौटनें के लिए सड़क विकास निगम ने छीन कर अधिकांश सड़कों को चौहरा और दोहरे मार्ग के निर्माण की तो दूर एकहरें 25 मार्ग बना कर तो वसूली शुरू कर दी जिसमें खंडवा बेतुल उज्जैन, कोटा जैसे मार्ग थे, इस प्रकार म.प्र. लोक निर्माण विभाग एक 15 सभाग जो राष्ट्रीय राजमार्ग का .. करते ये पूर्ण रूप से कार्य विहीन कर दिए गए, अब इन एएके 15 संभागों बंद कर.. में समहितकर दिया जाएगा, जबकि पूर्ण में जैसे सारे राष्ट्रीय राजमागों के उन्नयन और .. पूरा धन केन्द्र से मिलता था, अभी केन्द्रिय सड़क निधि से मिलने वाले रु. 1000 करोड़ से ज्यादा का धन जो राज्य व अन्य सहायक मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाले मार्गो के विकास उन्नयन और रखरखाव के लिए मिलता था, सारा कार्य म.प्र. लो.नि.वि. के इन 15 संभागों को दकर इन पर वेतन मंत्रों के रूप में किए जाने वाले खर्च भरपूर फायदा अभी भी लिया जा सकता हैं, और लिया जाना चाहिए, ताकि ये वर्षों से स्थगित एएके 15 संभाग पूर्णतः कार्यशील रहकर कार्य कर सकें। अभी यह ध्न लो निविके भवन पथ के प्रदेश के सभी संभागों को लिए रह हैं। जबकि प्रदेश के 55 से ज्यादा संभागों के पास राज्य सड़क निधि, मंडी निधि, नाबार्ड के पूर्व से ही ढेर सारे कार्यों के साथ प्रदेश के सभी शासकीय के निर्माण, उन्नयन रखरखाव के अरबों रु. के कार्य थे। जहां तक वर्तमान के पं. मंत्री कमलनाथ सवाल हैं, तो ये धूर्त जालसाज उस समय 1977 में छिंड़बांडा से कांग्रेस के संसद होने और चुनावजीत चुका था, जब पूरे उत्तरी भारत में कांग्रेस साफ हो चुकी थी, इसके विपरीत इस धूर्ते ने चिंदवाड़ा में हिन्दूस्तान लीकर व उसकी सहायक कार्यों वाली तालीफे लगवाने के अतिरिक्त तब से अभी तक सांसद होने की दम पर प्रदेश का भरपूर जालसाजी पूर्ण तरीके सेन केबल दोहन किया तथा साथ ही प्रदेश की ओर नोंच एसोट में कोई कसर नहीं छोड़ी जैसी कि कांग्रेसी गिरोह के डकैतों की .. रही हैं। वर्तमान में भी प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च किए जाने वाला रु. 5-6 अरब तो बचाय ही, दूसरी तरफ सारी सड़कों के चौड़ी करना और चौहरी करने के नाम पर अगले 15 से 20 वर्ष के लिए प्रदेश की सड़कों पर लूट और वसूली का लांडव करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपकर बीओपी के ठेकेदारों को सौंप दिया यहां तक कि इंदौर देवास बाईपास 55 कि.मी. जो पूर्ण से ही 4 टेन हैं और यातायात का भारी दवा भी नहीं हैं, इसके विपरित लूट वसूली और मांग टोल टैक्स वसूलने के लिए 6 लेन बनाकर टोल लगाने और दूसरे ठेकेदारों की कमाई का तांडव कर रहा हैं, इसलिए ताकि इंदौर देवास से गुजरने वालों से भी वसूली की जा सके।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूरे राष्ट्र को नक्सलाईट बनाने की तैयारी

७६ सीआरपीएफ जवानों की हत्या भी देतेवाड़ा की जमीनों को हथियाने, आदिवासियों, ग्रामिणों का निदियतापूर्वक दमन करने का ही परिणाम था। अब जबकि कांग्रेसी कमीशनखोर गिरोह राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम्ष्ठ को लेकर लागू कर रिलांयस और आईटीसी व अन्य को पूरा खाद्य उद्योग सौंपेगा ताकि इन कमीशन खोरों को अरबों रु. प्रतिमाह का कमीशन पूरे देश से मिलता रहे, बदले में चाय-पानी, दूध, गेंहू, चावल, घी, शक्कर, तेल आदि पूर्ण उद्योग पर इन दोनों धूर्त जालसाज कंपनियों का कब्जा हो जाए, इस अधि.०६ के अनुसार फिर कोई भी उप्रादक किसान अपनी फसलों से लेकर, सब्जीभाजी आदि को भी इन बहुराष्ट्रीय कं. को उनके खेत पर ही बेंच दे, उनके भावों में, फिर से गुना लाभ वसूलते हुए अपने ही रिलांयस फ्रेश आईटीसी चौपाल पर अपने भावों में बेचेंगे।फिर ठेले, खोमचें वाले, चाय कचोड़ी पकोड़ी वाले सब बंद सभी खाद्य तल, रिलांयस आदि टीसी मेक्डोनल्स की केंटिनों और दुकानों पर ही मिलेगा, यदि अन्य कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री का परिवहन भी करते पकड़ा गया तो रु. २५०००/- से लेकर रु.२ लाख तक का दंड भुगतेगा।

अभी जो मिलावट पर मृत्युदंड की बात कर रहे है राजनेता सब न केवल बेमानी है। वरन इन कंपनियों की मिलावटी सामग्री बेचने से मृत्यु भी हो जाएगी तो न्यायालय में वर्षों चक्कर काटने के बाद अधिकतम रु. ५ लाख का दंड भरना होगा सजा की बात तो बहुत दूर,अब जब पूरे देश करोड़ों खाद्य उद्योग से जुड़े, ठेलेवालों से लेकर मिठाई दुकानों तक, छोटे-मोटे लाखों उद्योग, टिफिन वाले आदि, तो भूखा मरता क्या न करता, मजबूरन नक्सली ओर माओवादी के साथ गुड़कर खुले में इन कंपनियों को लूटेंगे आम छोटे-बड़े शहरों में, भी स्वाभाविक है सारा सरकारी तंत्र इन पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कं का गुलाम होगा, क्योंकि वो दोनों हाथों से लूटकर एक हाथ से सरकारी अधिकारियों कलेक्टर से लेकर पुलिसिये कांस्टेबलों को अपनी सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त वेतन देंगे और सारा सरकारी तत्र उनके उपयोग के लिए जनता का दमन करेगा, इन दमनकारी नीतियों का फिर एक मात्र विकल्प होगा हथियार उठाकर ऐसे क्रांतिकारी मंचों से मिलना, ताकि वो भ्रष्टतंत्र से बदला ले सकें, दूसरी ओर इन कंपनियों ने किसानों से जमीनें हड़पने और उन्हें उनकी जमीन पर हीबधुआ मजदूर बनाने के षड़यंत्रों के तहत किसानों से कृषि भूमि के पट्टे पर लेने के लिए केन्द्र व राज्यसरकारों से कानून भी पास करवा लिए है। उप्र, मप्र मे इस तरह से कृषि भूमि हथियाने, भूमालिक को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए सैकड़ों ठहराव पत्र हस्ताक्षीरत हो चुके है। उन पर बीटी,जीएम फसलों को लेना और बोना शुरु कर दिया गया है। टमाटर, भिंडी व अन्य कई सब्जियों की देशी मूल प्रजातिया का नष्ट होनां शरद पंवार की कमीशन खोरी का ही परिणाम है।

ग्रामीणों में इन कांग्रेसी सत्ताधीशोंके षड़यंत्रों से आक्रोश न भड़के और उनके षड़यंत्र विफल न हो जाए ,म.गां. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) गरीबी रेखा से नीचे वालो को ३५ कि. गेहूरु २,चावलं रु. ३,१ प्रतिकिलों में देने के षड़यंत्र के पीछे गहरी दूरगामी बड़ी साजिश है, ये एक मुश्त इन बहुराष्ट्रीय कं. से अरबों रु.सौधा कमीशन उकार जाए शासन के करों की वसूली गई राशि से ग्रामीणोंकोरोजगार देकर और सस्ता गेंहू देकर गरीबों का पेट भरा रहे, जनता तो भूखी मरने के लिए पैदा हुई है। नक्सली बने तो पुलिस और सेना का उपयोग कर विरोध करने वालों को हर वर्ष १०००-२००० मार डालेंगे तो दहशत में आवाज भी नहीं आएगी।

पृष्ठ ८ का शेष

महिला आरक्षण या शोषण

इसका दूसरा पहलू देखें कि उप्र में जहां एक तरफ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी फैली हुई हुई है वहीं दूसरी तरफ वहां की मुख्यमंत्री आया वही अपने बसपा के गुंडो से भारी चंदा उगाही कर नोटो की माला पहन रही है। उस मतलब नहीं प्रदेश की समृद्धि से उसे मतलब है अरबों रु. की मूर्तियां पूरे-प्रदेशें लगवाने से, जब अनारक्षित स्थिति में यह हाल है, एक महिला मुख्यमंत्री बन जाती है, तो उसे अपने प्रदेशकी महिलाओं के घर चूल्हा जला भी या नहीं के विपरीत हो प्रदेश की जनता से वसूले करों से, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा वसूले गए धन से मूर्तियां लगवाने और नोटों की माला पहनकर अपनी देखती है, तो जब ३३ प्रतिशत मायाए आरक्षित होकर संसद में पहुंचेगी, तो वह संसद कम राष्ट्र का चुने हुए प्रतिनिधियों का नाइट क्लब ज्यादा होगी जहां पहुंच कर जनता की सुख, समृद्धि और विकास की बातों से दूर अपनी मौज-मस्ती और अय्यासी का अड्डा बन जाएगा।

प्रथम पृष्ठ का शेष

वर्ल्ड हेल्थ आरगेनाइजेशन- बनाम विश्व स्वास्थ्य बिगाड़ो संगठन विश्व में मानव स्वास्थ्य की रक्षा

असली उद्देश्य- अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दवाएं बेचने के लिए माहौल तैयार करना दहशत फैलाया, एड्स हेपेटाइटिस की ए से जेड की श्रृंखला इनकी तरह अपने यहां कार्यक्रम चलाए तो पर्यावरण सुधारने के नाम पर उनके उद्योगों को बंद करवाना, उनके विकास कार्यक्रमों को रोककर अपनी मशीनें और माल खरीदने को विवश करना ये इस संगठन की प्रत्यक्ष और परोक्ष कारस्तानी है।

स्वाइन फ्लू- सब इन्हीं धूर्तो की बनाई हुई बीमारियां हैं बदले में खरबों रुपए के टीके और दवाइयों पूरी दुनिया को बेची और अपनी दवाओं के प्रयोग से एशियन अफ्रीकन, राष्ट्रों की पूरी मानव आबादी को कमजोर, नपुंसक नकारा बनाने, उनके वास्तविक रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर चिकनगुनिया जैसे रोग फैला कर करोड़ों को असमय मौत भेंट की। प्रोटीन्स, विमामिन्स के नाम दुनिया को पिछले 50वर्षों से शब्दों के जाल में उलझा इसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अरबों रुपए की कमाई कर रही हैं।

एफ.ए.ओ.- फुड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन-

यू.एन.एस.सी.-युनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्

विश्व के देशों में सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा का ध्यान रखना।

वास्तविकता- विश्व की सुरक्षा के नाम पर उनकी आतंरकि सुरक्षा में हस्तक्षेप करना, हड़काना, डराना धमकाना।

यूनेप-युनाइटेड नेशनस इंवायरमेंट प्रोग्राम-

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम-

उद्देश्य विश्व के पर्यावरण की रक्षा करना

वास्तविकता- स्वयं पर्यावरण बिगाड़ना, यदि दूसरे देश

डंडप- युनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

आई.ए.ई.ए.- इंटरनेशनल एटमिक एनर्जी एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ

इ.को.ज.- इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (अंतर्राष्ट्रीय कानून)

इ.एच.- इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स कमीशन

- अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

डब्ल्यू टीओ- विश्व व्यापार संघ वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन

साप्ताहिक समय माया

विधायकों के लिए जनहित नहीं स्वहित पहले

प्रश्न लगाना-वापस लेना, कमाई का जरिया

विधानसभाओं में भीचलने लगा है, प्रश्न लगाने के पीछे पैसा

भोपाल-जनता के चुने हुए प्रतिनिधी विधायकों और सांसदों को चुने जाने के बाद तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितने जिम्मेदार होते है, जनता ने सांसदों के नोट कांड में हरामखोर, जालसाज सांसदों को कुछ वर्षों पूर्व सीधे ही टीवी चैनल्स पर देख लिया है, अब प्रदेश के विधायकों को देखें इस संबंध में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार में जानकारी मांग कर कि किस विधायक ने पूर्व की विधानसभा में और वर्तमान विधानसभा में प्रश्न वापिस लिए, में विधानसभा ने मांग विधायकों के नाम और कितने प्रश्न वापिस लिए की जानकारी दी है, पर किस विभाग या मंत्रालय से संबंधित थे नहीं बताया ।

इस संबंध में हम पाठकों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बता दे, कि अधिकांश विधायक जो एक नं. के जालसाज भ्रष्ट, होने के साथ न तो स्वयं के अधिकारों को जानते है, न ही तो कुछ करने की तैयारी में जब तक उन्हें किसी भी काम को करने, यहां तक कि प्रश्न लगाने में, भी उनका अपना निजी व्यक्तिगत हित साधन न हो तो प्रश्न लगाने की तो दूर वरन् उसका क,ख,ग भी नहीं जानते, दूसरा विधायक का चुनाव जीतकर तो हरामखोर, धूर्त जनता की सेवा के लिए नहीं वरन् अपना स्वार्थ सिध्दी, कमाई और लूट खसोंट के लिए लाखों रुपए खर्च कर, अपनी पार्टी से टिकिट झटकते है।फिर गाहे बगाहै करोड़ों खर्च कर धन,बल,छल से चुनाव जीतते है। फिर अगर उनकी पार्टी को सत्ता मिली तो रु. का दस लाख नहीं तो रु के ५० से १०० तो कमाएंगे ही, जहां तक प्रश्न लगाने का सवाल है, तो इन्हें तो शासन के विभागों का न तो एबीसीडी आती है, न ही यें पढ़ना चाहते है।तो फिर ये विधानसभा में अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करवाएंगे स्वाभाविक है पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर ये पत्रकारों तक के चक्कर लगाते है। तो पार्टी का उपयोग अपने कुकर्मो को ढांकने, कमाई वैध-अवैध तरीकों से करने के लिए विधायक की धौंस कपट शक्ति का उपयोग करते है। इसके माध्यम से वैध-अवैध तरीकों से कमाई में जुटे रहते है।अब बचे पत्रकार तो ९०प्रतिशत पत्रकारों का काम उनसे पैसे झटक कर उनकी तारीफें, उद्घाटन की फोटों छापते रहते है। इनको फिर चाहिए पड़ते है खोजी वास्तविक पत्रकार जो इनके विधानसभा में प्रश्न पूछवा कर सत्ता पक्ष को सकते में डाल दें, संबंधित मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी बुरी तरह से उलझ जाएं, जब बात इस स्तर पर पहुंचती है, तो संबंधित विधायक से उसके क्षेत्र के अधिकारी यदि मोटी रकम दे देते है जो की विधायकों का मूल उद्देश्य होता है।फिर स्वयं सत्ताधीश मंत्री भी प्रश्न न लगे इसलिए लेन-देन कर मामलों

के उपर ही सुलझाने की कोशिश करते है। जब सौंदा नहीं पटता तो ही प्रश्न सदन के पटल पर पहुंचता है। पटल पर पहुंचने पर भी सौंदे बाजी हो जाती है, तो जान बूझकर स्वयं प्रश्न के समय सदन से ही अनुपस्थित हो जाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता क्या सोचेगी और मिडिया में मामला कैसे उछलेगा।

दूसरी और वर्तमान विपक्ष की नेता जमुना देवी से लेकर अन्य अनेकों विधायकों, मंत्री से सौदेबाजी कर स्वयं ही ये धूर्त, हरामखोर जालसाजों, की फौज बड़े से बड़े मामलों को भी ड़कार जाती है, धन के बदले में, साथ ही प्रश्न लगाने की चमक धमक के बदले में संबंधित जिम्मेदार से स्थायी महीना वसूली व भाड़ में गया भ्रष्टाचार और जनहित।

अधिकांश होशियार विधायक प्रश्न लगाने की अपेक्षा प्रश्न आते ही सौंदे बाजी शुरु कर वसूली कर खेल खत्मकर देते है।यही कारण है, कि वर्ष के ३६५ दिन में से विधानसभा में ९० दिन भी, कार्य नहीं होता कुल मिलाकर ५०-६० दिन में कुल सत्रों मे भी अधिकांश भाजपा के आने के बाद समय पूर्व ही सत्रों को विपक्ष की नेता को समझाकर सत्र समापन कर दिए जाते है। जिन पत्रकारों से विधायकों की जान पहचान भी है तो ये विधायक उन पत्रकारों के कार्यालयों में बैठकर बिना दारु पिए प्रश्न नहीं उठाते है।अर्थात पत्रकारों को भी इनसे प्रश्न लगवाने के लिए रु.१०००/- से २०००/- तक दारु-शारु और खिलाने पिलाने पर ही ये प्रश्न विधानसभा सत्र में उठाते है। उठाने के बाद भी लेन-देन हो गया संबंधित मंत्री सचिव या अधिकारी से तो भी प्रश्न वापिस ले लेते है, या सदन से गायब हो जाना इन हरामखोरों का पुराना शगल होता है।

स्वाभाविक है, पत्रकारों द्वारा किया गया प्रश्न न केवल पूरी सत्ता को हिला देता है, तो दूसरी और विधायकों की बुद्धिमता के साथ जनता में और सत्ताधीशों में भी एक जुझारु राजनीतिज्ञ की छवि उभरती है, जो कि जीवन और राजनीति का भविष्य भी निर्धारित करता है।पर ये इसके बदले में पत्रकारों को हर प्रश्न पर रु. १०००/-से २००० की स्वागत के नाम से चोट पहनाने से नहीं चूकते जबकि ये विधायक होने के नाम पर इस प्रकार वसूली करने से पत्रकारों से भी नहीं चूकते। जबकि पूरे देश में विधायक सभी विधानसभाओं पत्रकारों के दम पर फूक फांक कर सत्ता पक्ष को उलझा कर अपने सिक्के चला पाते है।इसके विपरीत जन हित के मुद्दों पर भी सत्ता पक्ष से, संबंधित अधिकारियों से प्रश्न लगाने के बाद भी वापस लेकर अपना मुंह तो बंद करवाते ही है।साथ ही उन विधायकों को भी हतोत्साहित कर अपने भविष्य पर भी ताला लगा देते है।

नीचे वह सूची है जिसमें विधायकों ने प्रश्न वापिस लिए

किस विधायक ने कब-कितने प्रश्न वापस लिए

वर्ष २००४-२००८

अंचल सोनकर १, हामिद काजी १, छत्रपतिसिंह २, अर्जुन पलिया २, राजेश पटेल १, रसाल सिंह २, सुशीला सिरोठिया १, राजनारायणसिंह पूरनी १, हरेन्दजीत सिंह १, छोटेलाल सरावगी १, सुखदेव पांसे ४, संध्या सुमन राय १, धरमू राय १, हरिशंकर खटीक १, डॉ.सोबरन सिंह १, युवराज विक्रमसिंह १, डॉ.आईएमपी वर्मा ५, राम गुलाम उइके १, उम्मेद सिंह बना १, राजेश पटेल १, कुंवर विजय बहादुर बुंदेला १, महेन्द्रसिंह चौहान १, रमाकांत तिवारी १, नारायण त्रिपाठी १, अजय सिंह १, संध्या सुमन राय १, महेन्द्रसिंह चौहान २, किशोरी लाल वर्मा १, पवेसिंह पारगी १,उम्मेदसिंह बना १, मनोज पटेल १, छोटेलाल सरावगी ३, छत्रपतिसिंह १, बोधसिंह १, रसालसिंह २, घनश्यामसिंह २, महेन्द्रसिंह चौहान ३, अर्जुन पलिया २, कुंवर विजय बहादुर बुंदेला २, राम प्यारे कुलस्ते ४, छोटेलाल सरावगी ९, गिरीश गौतम १, रविन्द्रसुका महाजन २, मधुकर हर्णे १, लवकेश सिंह १, उम्मेद सिंह बना १, छत्रपति सिंह १, बोध सिंह ३, प्रदीप जायसवाल ३, दिलीपसिंह परिहार १, हरिशंकर खटीक १, सोबरन सिंह १, दीपक जोशी १, सोबरन सिंह १, छत्रपति सिह १, छत्रपति सिंह १, मधुकर हर्णे १, छत्रपति सिंह १, सज्जन सिंह वर्मा २, राम गुलाम उइके १, नानालाल पाटीदार १, राजेश पटेल २, छत्रपति सिंह १, गिरिजा शंकर शर्मा १, सुखेदव पांसे २, तुलसी सिलावट १, दीपक जोशी १, सरोज बच्चन नायक १, रामदयाल प्रभाकर १, सोबरन सिंह १, तुलसी सिलावट १

वर्ष २००९ में

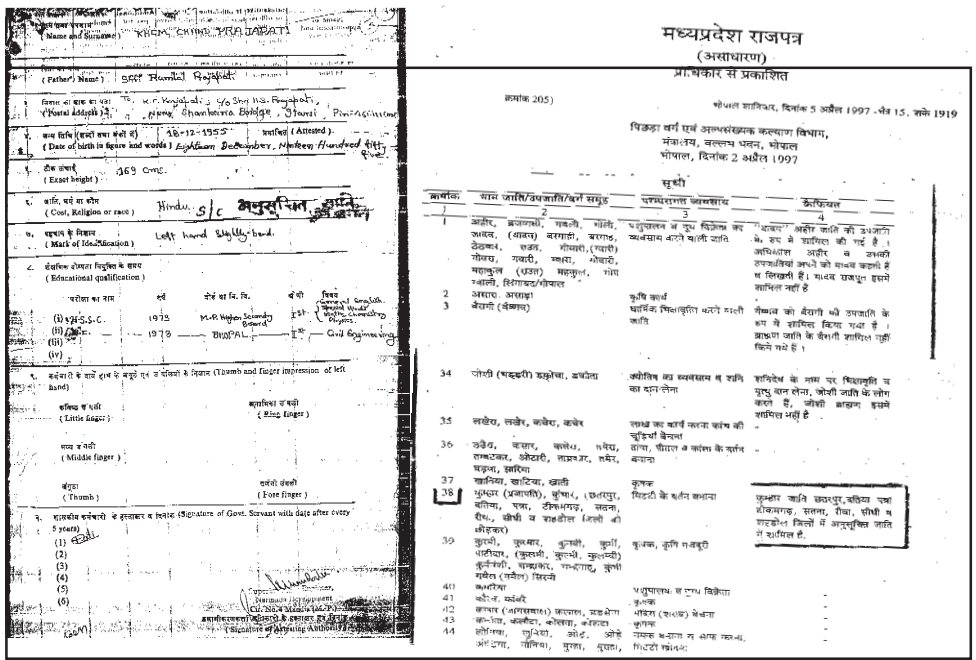

जुलाई अगस्त सत्र तक

शिवमंडल सिंह तोमर १, ठाकुरदास नगावंशी २, अजय यादव १, दीपक जोशी १, चैतराम मानेकर २, जेवियर मेडा १, यादवेन्द्र सिंह १, महेन्द्र सिंह १,ध्रुवनारायण सिंह १, विजयपाल सिंह १, संजय शाह २, गिरिजाशंकर शर्मा १, पांचीलाल मेडा १, नरेन्द्र त्रिपाठी १, मोतीलाल तिवारी १

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से प्रधान संपादक

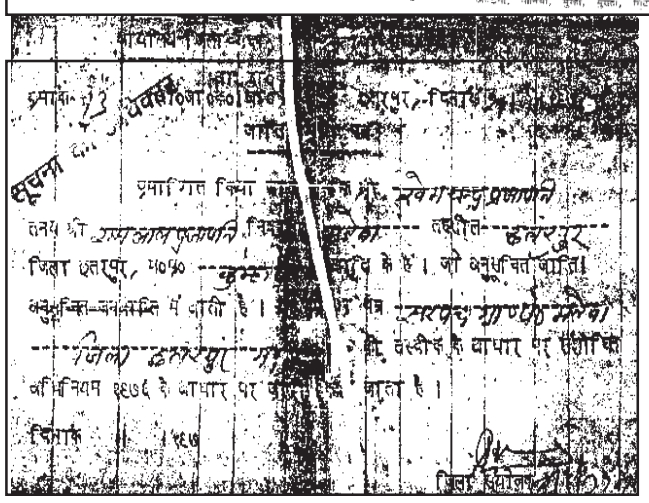

जल संसाधन जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमुख अभियंता

भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्ट जालसाज शीर्ष पद पर

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल । म.प्र. जलसंसाधन के प्रमुख अभियंता पद पर सुशोभित किए गए खेम चंद प्रजापति का जाति प्रमाण पत्र, जिसमें इसने पिछड़ा वर्ग को काटकर अनुसूचित जाति कर आरक्षित वर्ग का लाभ लेते हुए १९७८ के बीई सिवि ने १९८० में विभग में नियुक्ति प्राप्त कर सहायक यंत्री से चलते हुए ३० वर्ष में ही प्रमुख अभियंता पद छल, बल, धन के दम पर प्राप्त कर लिया इसके दूसरी और सामान्य वर्ग के सहायक अभियंता अभी भी एक भी पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सके, जबकि सैंकड़ों सहायक अभियंता सेवा निवृत्ति की कगार पर पहुंच गए, पर शीर्ष पर ... गिद्ध नेताओं, प्रधनमंत्री कानून मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इस बात से कोई सरोकार नहीं, एक तरफ उच्च शिक्षित प्रतिभाशाली, प्रतियोगी परिक्षाओं की गलाकाट प्रतियोगिताओं से चुनकर इंजिनियर, अधिकारी कर्मचारियों को २०-३५ वर्ष तक एक भी पदोंन्नति नहीं दूसरी तरफ वोटों की राजनीति के फेर में आरक्षण का लाभ लेकर डिग्रीयां लेने वाले, नियुक्ति प्राप्त करने कम शिक्षित चारों तरफ लूट खसोंट और भ्रष्टाचार कर धन कमा कर कैसे शीर्ष पद पर पहुंच जाते है, और जनता व प्रदेश की वास्तविक उन्नति को बाधित कर तांडव करते है।

जालसाज खेम चंद प्रजापति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक शिकायत की प्रति जो हमें प्राप्त हुई भोपाल से वह प्रस्तुत है दूसरी तरफ भ्रष्ट मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव, सचिव ऐसे भ्रष्टों, जालसाजों की कमजोर कड़ीयों का दबाकर अपने पास रख आसानी से ब्लेक मेल करते हुए दोनों हाथ वसूली करते है।जान बूझकर ऐसे जालसाजों को सुशोभित कर कमाई का जरिया बना लेते है। इसलिए शीर्ष पर .... जालसाज धुर्तो को कमाइ के लिए ऐसे ही जालसाज धूर्त पसंद आते है, जिसकी सत्यता का नमूना प्रधान सचिव पद पर जुलवानिया के पूर्व विराजे अरविन्द जोशी पर पड़े आयकर के छापे पकड़े गए रु. ३ करोड़ नगद और रु. ५०० करोड़ का बेनामी कारोबार के कागजात सत्यता सिद्ध करते है। बेशक वो अरविन्द और टीनू जोशी की खोपड़ी को एक बाल भी नहीं था, वर्तमान में ... प्र.स.रा. श्याम जुलवानिया जो वर्तमान में जल संसाधन में वसूली के लिए ईमानदार होने का नाटक कर सभी अभियंताओं की लगाम कस रहा है, तो मात्र मोटी नोंच खसोंट के लिए यदि ईमानदार है प्र.स. जुलवानिया प्रजापति को निलंबित कर जांच... कर सेवाएं समाप्त करें, तो अपनी सत्यता को सिद्ध कर पाएंगे।

प्रति *दिनांकः 30.04.2010*

श्री मनीश सिंह जी
डायरेक्टर पाइक्यू (विश्व बैंक)
पाइक्यू भवन
जल संसाधन विभाग
कोलार गेस्ट हाउस के पीछें,
कोलार रोड़-भोपाल (म.प्र)

विषयः- फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारें इंजीनियर इन चीफ बनने की जांच का निवेदन।

सन्दर्भः- श्री के.सी. प्रजापति ई-इन-सी जल संसाधन विभाग

महोदय, जी

निवेदन है,कि कृपया जल संसाधन विभाग के प्रभारी इंजीनियर इन चीफ श्री के.सी. प्रजापति के जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति कुम्हार) एवं सेवा पुस्तिका के अनुसार स्थायी पते की स्वयं ही जांच करें एवं विवेकपूर्ण निर्णय किया जावे कि क्या ऐसे फर्जी, झूटे एवं मक्कार को इतना महत्वपूर्ण यह दिया जाना चाहिए?

महोदय जी, ध्यान रखने की बात हैं,कि प्रजापति (कुम्हार) जाति छतरपुर में अनुसूचित जाति हैं एवं होशंगाबाद में ओ.बी.सी. हैं। लाभ लेने के लिए छतरपुर से जाति प्रमाण पत्र बनाया हैं, वह भी नौकरी में आने के बाद।

श्री के.सी. प्रजापति जो मूलः इटारसी (होशंगाबाद) के रहने वाले हैं, ने सेवा में आने के पश्चात छतरपुर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया एवं प्रमोशन लेकर अपने सीनियर के भी आफीसर बन गए।

आपको ईमानदार एवं सक्षम मानकर यह निवेदन किया जा रहा हैं कि भ्रष्ट एवं मक्कार को पद से हटाकर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र क जांच रिपोर्ट आने तक निलंबित कर किसी ईमानदार को इंजीनियर इन चीफ बनाया जावें।

भवदीय
(अरविंद सिंह) पत्रकार
सी-8, शास्त्री नगर
समीप जवाहर चौक,भोपाल

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव जलसंसाधन विभाग म.प्र. शासन भोपाल।

2. समस्त चीफ इंजीनियर जल संसाधन विभाग म.प्र. शासन। की ओर से सूचनार्थ प्रेषित। कृपया मक्कार एवं भ्रष्ट के.सी. प्रजापति को पद से हटाने के लिए उचित कार्यवाहीं करें। धन्यवाद।

3. श्री मान कलेक्टर-भोपाल (म.प्र.)

श्री के.सी. प्रजापति कार्यालय प्रमुख आयकट काड़ा प्रथम तल सतपुड़ा भवन भोपाल में आज तक अपने कार्यालय के कर्मचारियों की सूची कलेक्टर कार्यालय भोपाल को नहीं भेजी हैं। इसी कारण आज तक इस कार्यालय से किसी कर्मचारी की इलेक्शन ड्यूटी नहीं लगी हैं। कृपया कठोर कार्यवाहीं करेंगे। धन्यवाद

महंगाई बजट १०-११, महंगाई बढ़ाने और भ्रष्टाचार से कमाई

- कुल खर्च रू.५१५०७.३१ करोड़-रू.२५००० करोड़ वेतन मत्रों श्शासकीय सेवाओं, रखरखाव, कार्यलयीन व्यवस्थाओं आदि में खर्च हो जाएगा, बाकी रू. ३१५०७.३१ करोड़ में से रू.२०००० करोड़ भ्रष्टाचार में हजम रू.११५०१.३१ लगभग में से रू.६००० करोड़ वास्तविक दर पर।

- कुल आगम आय रू. ४३४४३.८२ करोड़ जो वास्तविक प्राप्त होने वाली आय का मात्र ५० प्रतिशत ही है। सबसे बडा स्त्रोत विकास या वाणिज्य कर से मात्र ५० प्रतिशत ही आय प्राप्त होती है, ५० प्रतिशत से ज्यादा चोरी जिसमें १० से १५ प्रतिशत विभागीय अधिकारी हड़प जाते हैं। इसक रू.८००० करोड़ संभावित है अर्थात इससे ज्यादा चोरी होती है।

- आबकारी से भी कुल ४० से ५० प्रतिशत ही प्राप्त होता है बाकी चोरी

- खनिज विभाग से मात्र १० से १५ प्रतिशत ही आय प्राप्त होती है ७० प्रतिशत चोरी और १० से १५ विभागीय निरीक्षक से मंत्री तक उकार जाते है।

- मुद्रांक व पंजीयन से भी ५० से ६० प्रतिशत आय होती है ५ से १० प्रतिशत पंजीयन कार्याय में बैठे ३४ पंजीयक से जिला पंजीयक तक बंदर बांट मै हजम

- केन्द्र से प्राप्त राज्यांश जो आय कर बिक्री कर कस्टम एंड एक्साइज, सेवा कर भी वास्तविकता में ३० से ४० प्रतिशत ही संग्रहित होता है,१० से १५ प्रतिशत आयकर कस्टम निरीक्षकों से लेकर आयुक्त और मंत्री तक भ्रष्टाचार में हजम कर जाते है। स्वाभाविक है राज्यांश केन्द्र सरकार भी आयोजन में उसी अनुपात में राशि आवंटित करता है।

- आयोन व्यय पर अनुमानित रू. २१९३९.१२ करोड़ में से रू.१५००० करोड़ बांट में और बचा हुआ ६९३९.१२ करोड़ वास्तविकता में ही खर्च होगा।

- आदिवास उपआयोजन में अनुमानित रू. ४०९०.४७ करोड़ में से रू.३५०० करोड़ बांट और भ्रष्टाचार में हजम हो जाएगा रू. ५९०.७७ करोड़ भी लक्ष्य पर मश्किल से खर्च होगा इतिहास और वर्तमान के सह योजन से भविष्य का परिहष्य है।

- अनुसूचि जातियों पर उपआयोजन बजट अनुमानित रू.२४९६..८६ करोड़ में रू. २००० करोड़ बांट और भ्रष्टाचार में समाप्त होगा, यह सब विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से लेकर सचिव प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री और मुख्य मंत्री तक बंटेगा।नगरीय अधोसंरचना बजट १०-११

- जवार लाल नेहरू शहरी पुर्ननवीनीकरण मिशन के अंतर्गत रू.३१८१ करोड़ स्वीकृत में से रू.२००० करोड़ भ्रष्टाचार में वास्तविक लक्ष्य पर खर्च रू. ११८१ करोड़ मुश्किल से ही होगा।

- एकीकृत शहर व मलिन बस्ती विकास में रू.२८० करोड़ में से रू.५०० करोड़ भ्रष्टाचार में रू.२६२ करोड़ लक्ष्य पर खर्च हो जाए तो प्रदेश क जनता का अहोभाग्य है।

उपरोक्त तीनों योजनाओं में १०-११ में रू.५२० करोड़ का आबंटन होगा स्वाभाविक है रू.३०० करोड़ हजम होंगे भ्रष्टाचार में रू. २२० करोड़ भी वास्तविक लक्ष्य पर खर्च नहीं किए जाएंगे।

- नगर विकास योजनाओं में रू. ५ करोड़ का प्रावधान किया गया है इंदौर-भोपाल मासरेपिड टांसपोर्ट जिसमें योना की जो बात बजट में कही गई है। तो पाठ ५ स्वयं सोचें कि इंदौर को २००५-०६ में आबंटित रू.८६८ करोड़ का क्या हुआ, शायद वो हजम हो गए पुनः नई योजना लाई जाएगी।

- प्रदेश की ग्रामीण शाला भवनों शुद्ध पेयजल योजना पूर्व से ही लागू है।

- म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को १०-११ के लिए रू.१०५१ करोड़ का प्रावधान है रू.६०० करोड़ कागजों पर खर्च होंगे और ५५१ करोड़ में से लक्ष्य पर रू.२५० करोड़ बाकी सरपंच, विधायकों, इंजिनियरों से लेकर सचिवों, मंत्री और मुख्य मंत्री तक बंटेगा।

अधिकांश केन्द्र की राशि को अपने बजट में लिखकर हजम करने के लिए पूरा तंत्र बजट को इस प्रकार बनाता है, ताकि किसी को भी तरीके से वास्तीवक्ता का अंदाजा ही न हो सके, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी रू.११ प्रति लीटर डीजल और पेटोल में जो वसूली की जा रही थी वह पहले सीधे केन्द्र नुसार की जाती थी अब कहे राज्यसरकार को ये मिलेगी उसमें भी अरबों रू. प्रतिदिन की आय प्रदेश को है। योजना में धन हो चुकी है।

बजट वैसे भी सारा आंकडों के बाजीगरी और वसूलीकर सेल है राजस्व की प्रगति आबकारी, रक्तदान वाणिज्यकर , मुद्रांक आदि से औसतन ५० प्रतिशत से ज्यादा नहीं होती है। ११० से २०६ हड़प ली जाती है। सर्वो में भी ५० प्रतिशत वास्तविक्ता में खर्च और ५० प्रतिशत डकारों या भ्रष्टाचार में हजम कर लिया जाता है।

(पृष्ठ ८ का शेष)

नंबर पोर्टाबिलीटी का नया...

क्योंकि आसानी से अपराधी एक नं. रखकर भी घड़ाघड़ कंपनियां बदलें और पकड़े जाने पर पुलिस भी जब पुछताछ करने जाएगी या करेगी तो मालूम पड़ेगा कि किसी भी कंपनी के पास उसका रिकार्ड ही नहीं मिल रहा हे, साथ ही पुलिस समझेगी नं. टाटा का है, टाटा से पूछ ताछ करेगी तो वहा बोलेगी बीएसएनएल में चला था १५ दिन पहले वहां जानकारी होगी जब बीएसएनएल से बात होगी तो वह बोलेगी आइडिया में चला गया था तो जानकारी देगी, वहीं हाल उपभोक्ता की सुरक्षा के मामले में भी होगा, किसी ने चमकाया धमकाया, तो वह नंबर से रिपोर्ट

लिखवाएगा तो फिर पुलिस की कबड्डी नाम कामया रहेगी।

बेशक टाई, दुरसंचार मंत्रालय एक तरफ आम उपभोक्ता को लूटने के लिए उनकी सुविधा के नाम डकेतों को सके दे पोश डकैती डाल कर हर दिन अरबों रूपए जनता से लुटवाएगा तो दूसर आपराधिक माफियाओं राजनैतिकों के अपराधियों, बड़े आपराधिक गिरोहों को बचाने, उन्हें जल्दी न ढूंढ पाने पुलिस को अपनी कारगुजारियां करने और लूटने का मौका भी प्रदान करेगा, ये नंबर पोर्टाबिलिटी का जादू सभी गिरोहों डकैतों को फायदा ही फायदा, भ्रष्टों को महीना वसूली दुगुनी, तिगुनी दूरसंचार के अधिकारियों को भी लाभ दूसरी ओर बीएसएनएल की चहुंदिशि बर्बादों, सरकारी कंपनी लूटनेखाने और नौंचने के लिए ही होती है। मरेंगे तो बीएसएनएल के कर्मचारी इसलिए इस षड़यंत्र को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए दूरसंचार मंत्रालय,टाई और सभी कंपनियां जुटी है नंबर पोर्टबिलिटी कुछ को तत्काल में नुकसान हो सकता है पर दीर्घावधि में फायदा ही फायदा।

क्षेत्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाए ताकि

कल सबको मिले जल आज हो व्यवस्था

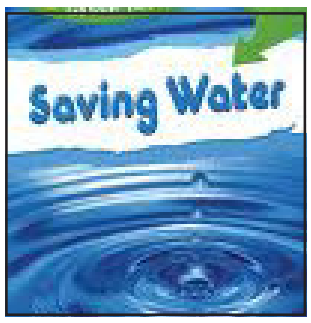

- राजनैतिक षड़यंत्रकारियों से जल वितरण और प्रबंधन व्यवस्था न केवल तुरंत जुड़ा लेनी चाहिए और पूर्व की तरह श्शासकीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को ही सौंप दिया जाना चाहिए, पिछले १० से ज्यादा

वर्षो में बड़ती समस्या और बहते जनता के आपसी संघर्षो से यह न केवल स्पष्ट हो गया वरन उच्च न्यायालय ने हाल ही में मई जून में दिए आदेशों में पुनः जिलाधीश और संभागायुक्त को व्यवस्था के रूप से चलाने के आदेश ने भी यह सिद्ध कर दिया है, कि इसे कदापि क्षेत्रीय प्रशासनिक स्तर पर सौंपा जाना न केवल घातक होगा वरन पुनः प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय को सौंपने पर पूरा ढ़ांचों की पुर्नसरंचना की आवश्यकता भी बढ़ और पड़ जाएगी।

- जल प्रबंधन मानसून के प्रारंभ से लेकर अगले मानसून आने तक वर्ष भर नियमित किए जाने के लिए आवश्यक मप्र लोकस्वस्थ यांत्रिकीय के अमियंताओं द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए पंच सरपंचों से लेकर, पार्षद, महापौर केवल शिकायतें और सुझाव देने तक ही उनकी औकात सीमित की जानी चाहिए।

- मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय जल वितरण का कार्य शहरों से लेकर गांवों तक अपने इंजिनियरों और नियमित कर्मचारियों से ही करवाएं वितरण का कोई भी कार्य ठेकेदारी फर्मो से न करवाए जाए, केवल टैकर ही ठेकों पर लिए जाए।

- मानसून के जल को न केवल कहने से रोका जाए बस, नदी, तालाबों, को गहरीकरण करवा कर उसमें जल संग्रहण बढ़ाया जाए ताकि भू-जल स्तर के गिरने के स्तर के तत्काल रोका जा सके।

- व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्तर पर लगे ट्यूबवेलों, कुंओं, बावड़ियों, के १५ से ३० मी. के दायरे में ही मानसून जल से पुर्नभरण हेतु तत्काल व्यवस्थाए की जाए, ताकि वर्ष भर जलमिलता रहे।

- मात्र ४० प्रतिशत नलों पर प्राप्त राजस्व को बढ़ाकर ९० प्रतिशत से १०० प्रतिशत पर लाया जाए, जिसमें दल, जाति, राजनीति से अलग हटकर लोक स्वा. यांत्रिकीय विभाग को ही वसूली सौंपी जाए।

- शहरों से लेकर गांवों तक बढ़ते कांक्रीट जंगल और गिरते भू-जल स्तर पर तत्काल प्रभावी स्तर से नियंत्रण कर संघन वनीकरण, वृक्षा रोपण की व्यवस्था की जाए, १८ वर्ष से उपर से हर व्यक्ति को दो पेड़ हर वर्ष लगाने और उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाए।

- आयकर वाणिज्यकर, बिजली के बिलों, की तरह नलों का बिल न भरने वाली की भी कुर्की की व्यवस्था की जाए, जल जीवन का आधार है, आयकर, वाणिज्य कर नहीं।

- अचल संपत्ति की बिक्री के समय स्थानीय संपत्ति कर चुकता भुगतान के बाद ही बिक्री मान्य की जाती है वैसे ही जल का बिल भरना भी अनिवार्य हो न।

- आने वो कल में सबको मिल जल की अतधारणा को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सामाजिक अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए ताकि बचपन से जल संरक्षण की अतधारणा मस्तिष्क में बनी रहे।

- कांक्रीट की सड़कों से बहने वाले पानी को क्षेत्रीय स्तर पर ही बने बगीचों में संचरन किया जाना चाहिए ताकि संघन आबादी वाले क्षेत्रों में भूजल स्तर सुधारा जा सके।

- नई आवासिय विकसित होने वाली कालोनियों, टाउनशिप में बगीचों की तरह ही, तालाबों की भी व्यवस्था और मुक्त भूमि रखी जानी चाहिए ताकि वहां वर्षा का जल, संचित किया जा सके, जिससे वहां खोदे गए ट्यूबवेलों, कुंओं से वर्ष भर जल मिल सके।

- भविष्य में किसी भी नई कालोनी, टाउन शिप को सार्वजनिक जल वितरण से जल प्रदाय नहीं किया जाए, हर कालोनी और टाउनशिप अपनी १जल प्रंबधन और नियमित वितरण व्यवस्था स्वयं करे तभी कालोनीनाइजर, टाउनशिप विकास करने वाली संस्था को तभी अनुमति की जाए, यह व्यवस्था क्षेत्रीय प्रादेशिक, राष्ट्रीय स्तर से विश्वस्तर तक पर लागू की जानी चाहिए।

म.प्र. ही नहीं वरन देश के अधिकांश नगरों में जहां नगर पालिकाओं और निगमों के हाथ में है जल वितरण का कार्य 40% से ज्यादा राजस्व नहीं मिलता, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है पाईप लाईन का मिट्टी में दबा देना, इससे यह मालूम ही नहीं पड़ता कि किस भवन में कितनी मोटी पाइप लाईन जा रही है। बदले में कितना राजस्व निगम पालिकाओं, जनपदों, पंचायतों को मिल रहा है। इस चोरी में स्थानीय पार्षद नेता स्वयं तो चोरी करते ही हैं।

वरन उनके चेले चपाटी, चंदादाता भी मोटी लाईनों से उसमें चोरी करते हैं। पाईप लाइनों को बकायदा गहरी, पक्की चौरकुटी पाईप लाईन साइज से डेढ़ गुना ज्यादा चौड़ी बनाकर बिछाई जाए तो पाईप मिट्टी से सड़ने से बचेंगे। साथ ही लीकेज, मरम्मत में भी आसानी होने के साथ ही उससे जल वितरण की सच्चाई का आंकलन और साइज के हिसाब से वसूली की जा सकेगी। आज नहीं तो कल सही राजस्व वसूली, रखरखाव, लीकेज की शीघ्र मरम्मत के लिए यह करना ही होगी। इससे आसानी से यह भी पता लगाया जा सकेगा कि कहां पर पाईप लाईन में नालों का गंदा जल लाईन में घुस रहा है।

भवनों में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों के हिसाब से प्रति व्यक्ति न्यूनतम 30ली. पानी प्रतिदिन के अनुसार जलकर की वसूली की जानी चाहिए न कि नल कनेक्शन की साईज के हिसाब से जिसमें 70% झूठे दस्तावेजों के आधार पर वसूली करने के कारण मात्र कुल जल वितरण का 40% राजस्व ही मिल पा रहा है। जिसका सारा भार मध्यमवर्गीय के कंधों पर ही होता है।

सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, विधायकों, पार्षदों, पंचों, सरपंचों को हर महीने के वेतन के पूर्व चालू महीने के जलकरों के भुगतान की रसीद जमा करने पर ही वेतन दिया जाए।क्रांकीट की सड़कों, क्रांकीट के आवासीय कालोनी के जंगले के बनाए जाने में पहले स्थाई पेयजल स्त्रोतों, जलाशयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो मूलभूत आवश्यकता है।

खेत का पानी खेत में की तरह वर्षा का छत पर गिरा पानी मकान के खाली पड़े हिस्से में जल पुर्नभरण कूप में आंगन में आजूबाजू में विशाल 8-10 फुट के नीचे टैंक में कालोनी का पानी कालोनी में जलाशयों में संग्रहित किया जाए।

मकानों, कालोनियों, टाउनशिप, शापिंग माल के नक्शे पास करने से पूर्व जल संग्रहण प्राप्ति के स्त्रोतों की भी समीक्षा की जाए। प्रदेशों और देश के जलसंसाधन विभाग को कृषि कार्य हेतु ही जल की व्यवस्था करने का ही नहीं वरन आवासीय क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों के जल की आवश्यकता की पूर्ति की भी जिम्मेदारी सौंपी जाए।

केंद्रीय जल आयोग सतही जल की ही नहीं वरन भूगर्भ के जल स्तर को स्थाई रूप से ऊपर उठाने, सतह के निकट लाने की व्यवस्था की भी लघु एवं दीर्घकालीन नियोजन करे, कृषि के लिए जल स्त्रोतों, आपूर्ति के साथ ही नगरीय जल आपूर्ति का अध्ययन, अवलोकन कर लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग पर भी न केवल नजर रखे वरन सलाह जवाब करने के साथ ही गंदे जल की पुर्नस्वच्छता और उपयोग भी निर्धारित करे।

(पृष्ठ ८ का शेष)

अमेरिकी गुंडे का ईरान में आतंक

केवल पान फेर देता है, वरन् रूस के पीछे खड़े होने से बराबरी की टक्कर देने की हूंकार, अमेरिका प्रशासन चाहे बुश का हो या ओबामा का भारी चुमन पैदा करती है।

२ ईरान में अगर चुनावों में धांधली हुई भी है, तो अमेरिका कौन उस राष्ट्र की संप्रमुता पर तुम्हें अंगुली उडान वहां ग्रहयुद्धं भड़काने का अधिकार किसने दे दिया यह वह जानबूझकर ईरान की छति बर्बाद करने और विश्व में नीचा दिखाने वहां की जनता में विद्रोह भड़काने और मुस्लिम समुदाय में छवि बनाने के लिए करवा रहा है।

अमेरिका दोगली प्रजाति के मानवों का देश है, फिर पूर्व के राष्टपति गोरी नस्ल के थे, पर बराक हुसैन ओबामा तो पूर्णतः संकर है, मिश्र में जाकर अलाह हो अकबर करता है तो दूसरी तरफ अमेरिका के हथियार उत्पादकों के इशारे तो पर नाचता है, और ओबामा की कब्र से बाहर निकालकर मुसलमानों को आंतकवादी बताने के लिए आतंकवाद का कहर ढाने का मय पैदाकर दक्षिण एशिया में हथियारों को बाजार गर्म करता है।

अमेरिका दोगले कभी किसी के सगे नहीं हुए, भारतीय धर्म शास्त्रों और पुराणों में दोगले प्रजाति के मानवों के बारे में जो वर्णित है, उस पर अमेरिकी वर्ण संकर बितकुला वैसे ही खरे उतरते है।

ईरान का आंतरिक संकट अमेरिका, ब्रिटेन का शिकार हो रहा है। ईरान ब्रिटिश राजनायिको को उनके इस कृत्य में शामिल होने, आंदोलनकारियों को सहयोग करते हुए पकड़े जाने के कारण तत्काल देश छोड़ने की चेतावनी दे दी है। अहमदी ने जाद को २ माह के लिए अमेरिकी, ब्रिटीश देशों के दूतावासों को संकट के चलते बंद कर देना चाहिए ताकि उसकी चिंगार को शोला बनने से रोका जा सके, चिंगारी को बुझाया जा सके।

भारतीय सत्ताधीश अमेरिकी सत्ता के गुलाम है चाहे तो बुश की हो या ओबामा की, मनमोहन और उसकी कांग्रेसी गैंग बुश ये अच्छी तरह से जानती है, कि ईरान पर अमेरिकी कब्जा होते ही सबसे ज्यादा असर भारतीय हितों पर सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामरक को मारी आफत पहुंचाएगा, यह शायद भारत के सत्ताधीश कांग्रेसी गिरोह के गुलामों का समझ नहीं आएगा, ये तो जब तक चोट नही खाते, इन को अक्ल की तो दूर निन्दा भंग नहीं होती।

३ पूर्व ईरानी राष्ट्रपति अहमदी नेजाद के पुनः राष्ट्रपति बना चुने जाने से उसको दक्षिण एशिया में ईराक ओर अफगानिस्तान की तरह ईरान में तांडव करने की योजनाा का षड़यंत्र विफल होने के कारण उसने अपनी ईरानी दूतावास इकाई के साथ ही ब्रिटेन व अन्य नाटो राष्ट्रों के साथ मिलकर गृह युद्ध भड़काने की चाल चली है। तेहरान व अन्य ईराकी नगरों में चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर दंगा भड़काया गया।इस भाग में घी झोंकने में सीएनएस,वीवीसी जो कि अमेरिकी सरकार और ब्रिटिश सरकार के मिडिया चैनल्स है, न सदा की तरह ही दक्षिण एशिया में अशांति फैलाने का कार्य किया, इस ग्रहयुद्ध को भड़काने देंगे के विडियोज लगाने, दिखने में गूगल के, युट्यूब, याहू ने भी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

अमेरिकी मुंड़े ओबामा को वहां अथियार निर्माता उद्योग पतियों, पूंजीपतियों जिन्होंने चंदा किया था इस बात के लिए दबाव बनाया।

म.प्र. स्वास्थ्य विभाग-डाक्टरेट इन भ्रष्टाचार

उज्जैन की अंकेक्षण रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की बानगी

अंकेक्षक भी ठेके पर आकर, छोटे पकड़ते है,बड़े गबन के लेनदेन पर चुप

उज्जैन। उज्जैन के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सूचना के अधिकार में प्राप्त अंकेक्षण रिपोर्ट में भी वैसे तो लाखों की खरीदी और जन धन के गवन के मामलों से भरी पड़ी है। यह भी वन जब की आडिट टीम आने के दो माह पूर्व सूचना देती है दूसरा आते है। आडिट टीम का मुखिया रू.लाख,५० हजार में बड़े गवन छुपाने और छोटे-छोटे गैर कानूनी कार्यो का वादा करता है। जब तक आडिट टीम रहती है। आडिटर्स को सुरा, सुंदरी से लेकर सभी प्रकार की घर के बाहर घर जैसी सुविधाओं वाली हो प्लेन में कहराया जाता है। प्रतिदिन के हिसाब से ५ से १० हजार तक का उपरी खर्चा प्राप्त होता है। इसके बदले में वो छोटे-छोटे गैर कानूनी, अवैद्य मुद्दों की सूची इस प्रकार तैयार करते है ताकि भ्रष्ट आसानी से बच निकलें। जबकि मप्र स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार उपर से मंत्री से लेकर प्राथमिक स्वा. केन्द्र तक और की पोस्टिंग से लेकर विभिन्न योजनाओं में धन बांटने जिसमें जनबी सुरक्षा योजना दीन दया स्वास्थ्य योजना जैसी योजनाओं का भी पैसा पाइप लाईन से पहुंचता है।

उज्जैन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की आडिट रिपोर्ट यहां यथ्नवत प्रकाशित की जा रही है। आंतरिक लेखा परिक्षण की इस रिपोर्ट पर ३ वर्षबाद भी कोई ठोस कार्रवाई भ्रष्टों के खिलाफ नहीं हो सकी है। अनाप-शनाप खरीदी समय बाघित दताओं की तो पूरे प्रदेश में पिछले ३० से ज्यादा वर्षे से भ्रष्टाचार विशेषज्ञ डाक्टर्स आंख भी कार्रवाई के न होने से ये सब निरंकुश हो लूट पाट में जुटे है। इन हरामखोरों को अपनी कमाई से मतलब रहता है, चाहे वो दवाएं किसी के काम आए न आए दूसरी तरफ रोगियों को ये शूटरों की फौज शासन के पास पैसा न होने दवाई न होने का रोना रोकर बाजार में दवाईयां खरीदने के लिए पर्ची लिखकर दुकानदारों से भी सीधा कमीशन डकार जाते है।

हर वर्ष पूरे प्रदेश में लगभग १ अरब से ज्यादा की दवाए खरीद कर नष्ट की जाती है। जिसकी सत्यता से अंकेक्षण रिपोर्टसे प्रगट होती है। यही कारण है कि इंदौर संभाग के आठों जिलों में से किसी भी नोंच खसोंट करने वाले खानों की फौज मुख्य चिकित्साधिकारी ने सूचना के अधिकार में आदेश देने के बाद भी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है।

अब यदि मप्र के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ निगाहें उठाए तो डॉ. योगीराज, डॉ. अशोक शर्मा जिन पर न केवल लोका युद्ध की कार्रवाईयां वरन आयकर के छापे भी पड़ चुके है। हाल ही में डॉ. अशोक शर्मा का निलंबन हमारे पत्रकार श्री सतीश भारद्वाज द्वारा विधानसभा के पत्रकार कक्ष में स्वास्थ्र्य मंत्री से यह पूछे जाने पर कि एक को सजा दूसरे को भ्जा देकर परूपात किया जा रहा है, पुनः निलंबित कर दिया गया था, बाद मे डॉ. अशोक शर्मा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आया और वहां संचालक के पद पर बैठे व्यक्ति के साथ मारपीट कर और कस में तोड़फोड़ कर पुनः कब्जा जमा लिया, जो यह सिल करता है भ्रष्टाचार की डाबरेट है स्वास्थ्य विभाग के सभी डाक्टरों के पास कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के माह ५/२००८ से अप्रैल २००७ तक की अवधि के लेखाओं के नमूना लेखा परीक्षा कार्यालय प्रधान महालेखाकार 'सिविल एवं वाणिज्यिक ले.प.' मप्र ग्वालियर के स्थानीय के स्थानीय, लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक ७.०५.२००७ से १६.०५.२००७ तक संपन्न की गई।

कार्यालय के अभिलेखों की पूर्व लेखा परीक्षा माह ७/०४ से ४/०६ तक की अवधि दिनांक १५.५.०६ से २४.५.०६ तक संपन्न की गई।

निम्नांकित अधिकारियों ने लेख परीक्षा अवधि में उनके सम्मुख दर्श अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के पद पर पदभार संभाला

क्रं	नाम अधिकारी	पद	पद अवधि
१	डॉ.आर.आर. जड़िया	मु.चि.स्वा.अधिकारी	१.५.०६ से १०.७.०६
२	डॉ.आर.पी. सिंह गेहरवार	मु.चि.स्वा.अधिकारी	११.७.०६ से २४.४.०७
३	डॉ.दिलीप नागर	मु.चि.स्वा.अधिकारी	२४.४.०७ से निस्तर

उक्त अवधि में निम्न अधिकारियों द्वारा अपहरण एवं संवितरण का कार्य किया गया।

क्रं	नाम अधिकारी	पद	पद अवधि
१	डॉ.आर.आर. जड़िया	मु.चि.स्वा.अधिकारी	१.५.०६ से १०.७.०६
२	डॉ.आर.पी. सिंह गेहरवार	मु.चि.स्वा.अधिकारी	११.७.०६ से २४.४.०७
३	डॉ.दिलीप नागर	मु.चि.स्वा.अधिकारी	२४.४.०७ से निस्तर

२. आंतरिक लेखा परीक्षण एवं पर्ययेक्षण

क. वित्तीय नियमों का अनुपालन तथा अभलेखों का रख-रखाव।

मप्र कोष संहिता भाग-एक के उपनियम २९१ के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने कार्यालय के अभिलेखों की माह के अंत में जांच कर अनियमितताओं एवं उनमें सुधार के प्रयत्नों की टिप्पणी सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। लेकिन उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है।

ख. आंतरिक लेखा परीक्षा

१. लेखा परीक्षा की अव्रत्ति अवधि में कार्यालय के लेखाओं की विभागीय लेखा परीक्षा आंतरिक परीक्षा दल द्वारा नहीं गई है।

२. लेखा परीक्षा की आव्रत्ति अवधि में कार्यालय के लेखों की लेखा परीक्षा संचालक कोष एवं लेखा विभाग के लेखा विभाग के दल नहीं गई है।

३. लेख परीक्षा अवधि के अभिलेखों का निरीक्षण विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया।

ग. पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति

लेखा परीक्षा के प्रारंभ में पूर्व परीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है-

क्रं	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि प्रतिवेदन जारी होने	लंबित कंडिकाएं
१.	२/२००२ से ५/२००३ -	६
२.	६/२००३ से ६/२००४ -	१,३,५,;सद्ध,८,;अद्ध,९,१०
३.	७/२००४ से ४/२००६ -	१,;कद्ध,;खद्धएख,;११द्धए ग,घ,२,३,४,५,६,७
		योग-३ १४-६ सब पेश

वर्तमान लेखा परीक्षा में लंबित कंडिकाओं की समीक्षा किए जाने पर लंबित कंडिकाओं क स्थिति निम्नानुसार रही-

क्रं	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	निराकृत कंडिकाए	वर्तमान लेखा परीक्षा प्रति.में शामिल	लंबित कंडिकाए लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन नमुना टीप
१.	२/०२ से ५/०८	६	-	- निरक
२.	६/०६ से ६/०४	५ स, ९	-	१,३,८अ, १०
३.	७/०४ से ४/०६	१ घ,३		१ क,ख,२, ग,२,४,५,६,७
३ योग		३		१,१ से सब पेश १० सब पेश है

लंबित कंडिकाओं का पूर्ण विवरण अनुलग्नक के में दर्शाया गया है।

कंडिका १. चिकित्सा विशेषज्ञ विहीन माधव डिस्पेंसर, उज्जैन में अस्थि शल्य टोमा, शिशु विभाग, गहन चिकित्सा विभाग, नाक, कान, गला विभाग के संचालन नहीं होने के कारण उपकरणों का उपयोग नहीं होने से उपकरणों के क्रय पर निरर्थक व्यय रू.१.२० लाख।

२००४ में अधिग्रहित १०० विश्वर का माधव नगर चिकित्सालय उज्जैन में निम्न विभागों के लिए इनखेर व्यवस्था की गई थी।

शिशु वार्ड, आर्थोपेडिक टोमा विभाग, ई.एन.टी.विभाग, आई.सी.सी.यू विभाग

उक्त चिकित्सालय में चिकित्सा विशेष्ज्ञ के पद पर रिक्त होने से यह वार्ड बंद पडे.हुए हैं जिसके इन वार्डो को आवंटन किए गए निम्न बेड का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है।

शिशु विभाग	१० बेड
अस्यि शल्य	१० बेड
आई.सी.सी.यू. वार्ड	५ बेड
एन.आई.सी.यू	३ बेड
ई.एन.टी.वार्ड	५ बेड
	३३ बेड

उक्त वार्ड बंद रहने से अन्त रोगियों की संख्या भी कम है। गत ४ माह में अंतः रोगियों की संख्या निम्नानुसार थी।

माह	रोगी संख्या	औसत
जनवरी ०७	१२६	४रोगी प्रतिदिन
फरवरी ०७	१३२	४ रोगी प्रतिदिन
मार्च ०७	१११	४ रोगी प्रतिदिन
अप्रैल ०७	२१६	७ रोगी प्रतिदिन

इस प्रकार १०० बेडेड अस्पताल में उपलब्ध शययाओं का उपयोग भी पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है।

इसके अतिरिक्त माधव नगर, चिकित्सालय उज्जैन में उक्त वार्डो के अन्तः रोगियों के उपचार हेतु संलग्न परिशिष्ट ग में वर्शित जो उपकरण क्रय किए गए वह भी व्यर्थ एवं अनुपयुक्त पड़े हुए है। जिसके कारण इन उपकरणों पर किया गया संपूर्ण व्यय निरर्थक एवं निष्फल हो गया। उक्त तथ्य लेखा परीक्षा में इंगित करने पर उत्तर में लिखा है कि माधव नगर चिकित्सा के विशेषज्ञ के पद भरने के संबंध में संचालनालय को अवत कराया गया है तथा प्रस्ताव भी भेजे गए है। मरीज उपलब्ध होने पर उपकरणों का उपयोग किया जावेगा। उक्त तथ्य शासन के ध्यान में लाया जाता है।

कंडिका २. वर्दी एवं चादर में क्रय में अनियमितता-राशि रूपए ८८ लाख एवं अनियमितव्ययी पूर्ण व्यय राशि रूपए ४४.३२ लाख।

म.प्र. शासन वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के ज्ञापन क्र. एक १२.१.९९.अ.दि. ११.९.१९९९ के द्वारा मप्र भंडार क्रय नियम १४ 'अ' में व्यापक संशोधन किए गए है। नवीन संशोधन के अनुसार प्राप्ति वर्ष लगने वाले वस्त्रों की मांग का आकलन करके प्रदाय आदेश ३१ मई के पूर्व आयुक्त, हाथ करघा मप्र भोपाल कपड़े की पूर्व आवश्यकता की पूर्ति हाथ करघा/मप्र खादी एवं ग्रामोंद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित वस्त्रों की इकाईयों से करावेंगे।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा आवश्यकता का आकलन किए बगैर मप्र राज्य पावर लूम बुनकर सहकारी समिति इंदौर से संलनपरिशिष्ट 'घ' में दिए गए विवरण अनुसार रूपए ६८ लाख की सामग्री क्रय की कई जिसमें से १३,७१,२०६/-रुपए की सामग्री संलग्न परिशिष्ट 'ड़' अनुसार सिविल डिस्पेंसरी नागदा, महीदपुर एवं अन्य डिस्पेंसर को अनावश्यक रुप से स्थानानांतरित कर दी गई जिसकी मांग भी प्राप्त नहीं हुई थी। तथा यह डिस्पेंसरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यक्षेत्र में भी नहीं आनी थी। उक्त राशि रूपए १३,७१,२०६ की वसूली सिविल सर्जन उज्जैन से नहीं की गई। इसके अतिरिक्त रुपए ३०,६१,६४० की सामग्री अनावश्यक रूप से एक वर्ष के अधिक अवधि से परिशिष्ट ड अनुसार व्यर्थ एवं अनुपयुक्त पड़ी हुई है।

इस प्रकार मप्र वित्त संहिता भाग-१ के नियम ११८ के विरुद्ध अनावश्यक रूप से अमितव्ययिता पूर्ण रूपए ४४,३२,८४६ /- का क्रय किया गया है एवं सक्षम अधिकारी को स्वीकृति से बचने के लिए क्रय आदेश टुकड़ों में जारी किए गए।

उक्त तथ्यों की ओर कार्यालय का ध्यान आर्कषित करने पर उत्तर में लिखा हे कि सामग्री का क्रय जिले के समस्त स्वास्थ संस्थाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सामग्री क्रय संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को भेजे गए है। लेखा परीक्षा उक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है। उक्त तथ्य शासन के ध्यान में लाया जाता है।

कंडिका ३. माधव नगर चिकित्सालय उज्जैन के टोना यूनिट हेतु क्रय की गई एंबुलेंस पर निष्फल व्यय राशि रुप १७.९७ लाख

भारत सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक जेड-२८०१६/९९/०२ निर्माण भवन/नई दिल्ली दि.२१.३.०५ द्वारा माधव नगर चिकित्सालय उज्जैन के उन्नयन हेतु रूपए १०१.९७ लाख की केंद्रीय सहायता प्रदाय की गई थी, जिसमें से १८लाख का प्रावधान टोमा के लिए २ एम्बूलेन्स क्रय करने हेतु किया गया है।

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाए मप्र भोपाल के पत्र क्र, डीएमएस/०६/१२१/दि. ३१.१.०६ द्वारा मेसर्स प्रेमाच मोटर्स लिमि.भोपाल से दो एम्बूलेंस वाहन क्रय की गई जिसका भुगतान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन द्वारा दि. २४.३.०६ को दिया गया। उक्त दोनों वाहन मार्च २००६ में प्राप्त किए गए। वाइन एवं उसमें लगाए गए उपकरणों की कीमत निम्नानुसार थी।

२ वाहन एच.एम. आरटीवी		१३,६५,५५६
ईसीजी मशीन	२ नग	६५,२००
पल्स मोनीटर	२ नग	१,०२,६४८
ऑक्सीजन सिलेन्डर	२ नग	१२,५६०
डी फेविलियर	२ नग	२,५१,१६०
		१७,९७,१२४

पिछले लेखपरीक्षा प्रतिवेदन '७/०४ से ४/०६' की कंडिका में उक्त वाहन मई २००६ तक उपयोग में नहीं लाया जाना बताया गया था, जिसके उत्तर में कार्यालय द्वारा भविष्य में उपयोग में लाया जाना बताया गया था, परन्तु उक्त अवधि के बाद भी यह दोनों एम्बूलेंस जिस उद्धेश्य के लिए क्रय की गई थी उसके लिए उपयोग नहीं किया गया। उक्त दोनों वाहन क्रमांक एमपी ०२-११६५ लेखापरीक्षा दिनांक एवं एमपी ०२-११६६ में तक निष्क्रय खड़ा हुआ है। दूसरा वाहन एमपी ०२ ११६६ का उपयोग दि.१५.०२.०७ से टोमा यूनिट से वाहन क्र एमपी ०२-११६६ के उद्धेश्य के विपरीत डाक्टर को घर से लाने ले जाने, डाक लगाने, सामान्य रोगियों को मुफ्त ले जाने हेतु अनाधिकृत रुप से किया गया। इस वर्ष के लिए वाहन १२०० किमी चलाया गया। इस प्रकार एक एम्बूलेंस निष्क्रिय रहने एवं दूसरा वाहन उद्धेश्यों के विपरीत चलाने से एम्बूलेंस एव उपकरणों पर किया गया व्यय रुपए १७.९७ लाख निरर्थक एवं निष्फल रहा।उक्त तथ्य लेखा परीक्षा में इगित करने पर उत्तर में लिखा है कि उक्त दोनों एम्बूलेंस का उपयोग टोमा यूनिट के लिए होना है जिसमें कोई बड़ा हादसा होने अथवा दुर्घटना होने पर घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एम्बूलेन्स का उपयोग किया जाता है वर्ष २००६-०७ में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे एम्बूलेंस का उपयोग किया जाता। एम्बूलेंस का उपयोग उद्धेश्य के विपरीत डाक्टर को लाने ले जाने, शासकीय डाक लगाने एवं सामान्य रोगों को मुफ्त लाने ले जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। टोमा यूनिट भी माधव नगर चिकित्सालय में चालू नहीं है। अतः यह वाहन अनावश्यक रुप से रखे हुए हे जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है।

म.प्र.सूचना आयोग...

७ पृष्ठ का शेष

उपायुक्त बैठते है। तीन वाणिज्य कर संग्रह, ३ अपीलेट, २ एंटी इवेजन ब्यूरों। अंकेक्षण, और ४ से ज्यादा मुख्यालय में बैठते है आठ के विरूद्ध अपीले भेजी गई थी, कौन सा उपायुक्त वाणिज्य कर है, उसे बचाने और अपने निकमेपन को छुपाने हरामखोरों ने पूरा और सही पता नहीं लिखा, दुसरा दुसरा जान बुझकर, संबंधित अधिकारी अनावेदक से लेन-देन कर प्रतियां कम होने का शिजूका छोड़ बचालिया गया।

अब किसकी फोटो कापी भेजे जाए, करोड़ों रु. का आबंटन उकारने वाले ये शूकरों की फौज के पास स्वयं की फोटो कापी मशीन है, यदि ईमानदारी होती तो ये लिखने की अपेक्षा इस अपील की फोटो कॉपी करवा कर कार्यवाही संपन्न करते, ये हरामखोर श्तानों की फौज बहुत अच्छी तरह से जानती है, कि अगर श्री अजमेरा अपीले भेज रहे है, तो अनावेदक सिर झुकाकर वहां अपील में सुनवाई के लिए पहुंचकर चढ़ोगा भी चढ़ा रहे है।अन्य या देवास में धारा ४ के पालन से अपीले घट कर नमा मात्र रह गई है।

यदि सूचना आयोग में बैठ सेवानिव्रत्त आयुक्तों की फौज में थोड़ी सी भी ईमानदारी जनता के धन से मिलने वाले वेतन के प्रति थोड़ी सी वफादारी निभाने क नियत होती तो ये शूकरों की फौज न केवल धारा ४ का पालन ५ वर्षों में हर सरकारी विभाग से करवा चुकी होती, साथ ही जनता के धन से होने वाली भ्रष्टाचार की होली के रंगों का अंदाजा कम से कम १ प्रतिशत जनता तो लगा ही सकती थी, इसके विपरीत जीवन भर डकैती और जनता के धन से लूट खसोंट करने वाले ३ आयुक्तों की बेशर्मी, बतमीजी और निकंमेपन का आयोग क कार्यशैली उत्क्रष्ट है, शाम ४ शासन की मांड गिरी करने अपीलार्थियों को हत्सोहित और मानसिक प्रताड़ना देकर परेशान करने आर कहने पर ये शूकर इकबाल अहमद कहता है, यहां से भी संतुष्ट नहीं हो तो उच्च न्यायालय में जाओ, वहां से जानकारी निकलवाओ कि सलाह नहीं देता जो स्पष्ट करता है, कि हमने जिंदगी भर भ्रष्टाचार और हरामखोरी की है, मरत दम तक यहीं और यहीं करेंगे।

सर्वशक्तिमान मप्र का आई.ए.एस इकबाल हांक रहा भाजपा का प्रशासन

इकबाल की धुन पर शिव के शासन प्रशासन का नृत्य

मु.मं.निवास से मंत्रालयों और प्रशासन में गिद्ध इकबाल की षड़यंत्रकारी शतरंज

सत्ता के गलियारों से लेकर प्रशासनिक वीथिकाओं तक एक ही सर्वशक्तिमान और दरबार के दमनकारी इकबाल सिंह बैस का नाम गूंज रहा है। नाम क्यों गूंज रहा है?यह सवाल अहम है। कौन है यह इकबाल, जिसके बिना पूरे प्रदेश में पत्ता तक नहीं हिलता? क्यों नहीं हिलता? कोई भी काम, कोई भी फाइल इनके इशारे के बिना सरकारी क्या कारण है कि इकबाल से बिना पूछे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह, उनकी धर्मपत्नि साधना सिंह, उनके साले, भाई-भतीजे कोई कदम नही उठाते? प्रशासनिक कार्य ही नहीं, कई महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले भी इकबाल सिंह की इशारे से ही होते है। इकबाल की षड़यंत्री चालो से मंत्री, विधायक विद्रोह करने की राह पर आ सकते है। शिव मंत्रिमंडल के अधिकतर मंत्री शिवराजका नाम सुनते ही छिटकते हैं। वे कहते हैं भाग्य कब तक साथ देगा कुछ काम तो करना पड़ेगा। चंद अफसरों के साथ मिटिंग-मिटिंग खेलने से चुनावी नैया पार थोड़े होगी। एक मंत्री कहते है दिग्विजय सिंह कंधे पर हाथ रख कर निपटाते थे और शिवराज बातों-बातों में। शालीनता का लबादा ओढ़कर वे किसी काम के लिए किसी का ना नहीं करते और काम किसी के करते नहीं। सत्ता मानव संभ्यता के अभ्युदय से लेकर वर्तमान और भविष्य में भी षड़यंत्रकारी, जालसाजों, चादूकारों का अड्डा रही है और रहेगी, शिवराज स्वयं प्रशासन न तो छात्र रहा है और न ही अनुभव यही अनुभव हीनता ने शिव को इकबाल की कठपुतली बना नाचने के लिए मजबूर कर अपनी षड़यंत्री शतरंज की विधात पर सजाकर यह बजीर किसी की दशा और दिशा में भार कस रहा है, जबकि शिवराज के पास मात्र एक घर चारों दिशाओं में ही चलने देता है। राजा मुख्य मंत्री उनकी शह से बाहर न चला जाए इसलिए इस षड़यंत्रकारी वजीर से भी अपने तीन शातिर वजीर जो पूर्त से ही भ्रष्टाचार के हरे-फेर विशेषज्ञ और प्रशासनिक अनुभवि शातिर है जिनमें अनुराग जैन एसपीएस परिहार विवेक अग्रवाल जैसे अधिकारी है।

प्रशासनिक वीथिकाओं में यह जुमला बड़ा प्रसिद्ध है कि शिवराज छींकने के लिए भी इकबाल सिंह की परमिशन लेते है। इकबाल सिंह के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, उसकी वजह मंत्रियों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों की नाराजगी है। एक मंत्री काव कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि इकबाल सिंह के कमरे की विडियों रिकार्डिंग करवाएं। वे मंत्रियों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों से किस तरह का व्यवहार करते है, इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। शिवराज सिंह के प्रदेश के पचहत्तर फीसदी से ज्यादा अफसर इसलिए नाराज है, क्योंकि उन्होंने इकबाल सिंह को माथे पर बिठा रखा है। प्रदेश के सभी मंत्रियों को इस अफसर ने पिछले कई महीनों से रुला रखा है। कारण है मंत्रियों के निवास पर उनके पर्सनल स्टाफ की नियुक्ति। हर नियुक्ति को इस व्यक्ति ने रोके रखा। मंत्री हैरान-परेशान रहे, लेकिन हुआ वही जो इकबाल सिंह ने चाहा। मंत्री विधायक मुख्यमंत्री से तो आसानी से मिल लेते है, लेकिन इकबाल से मिलना उनके लिए टेढ़ी खील है।सर्वशक्तिमान इकबाल सिंह ने भले ही पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ली हो, लेकिन वे ही असीली मुख्यमंत्री हैं। इकबाल कैबिनेट में भी कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), राज्यमंत्री, उपमंत्री से लेकर संसदीय सचिवों तक की भागीदारी है। आईए, हमबताते है आपको, कौन है इकबाल सिंह की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में-

१ अनुराग जैन- मृदुभाषी, सौम्य व्यवहार की धनी आईएएस अफसर अनुराग जैन वैसे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिव है, लेकिन वे असली जवाबदेह इकबाल सिंह बैस के प्रति है। इकबाल के कहने पर ही अनुराग पूरे समय मुख्यमंत्री को सिर्फ मीटिंग्स में उलझाए रखते है। चाहे मीटिंग स्वास्थ्य विभाग की हो, पंचायत क अथवा विकास के मुद्दे पर कोई भी विषय पर हो। मुख्यमंत्री को ये महाशय एक मीटिंग में घ्टों व्यस्त कर देते है। मामला मंथन का ही क्यों न हो, आप खुद देख लें, सीएम ने अब तक कई घंटे उसमें खपा दिए। ये भी एक साजिश है। सीएम को मीटिंग में व्यस्त रखों और बाकी सारी फाइलें इकबाल भाई निपटा लेंगे। कुल मिलाकर इकबाल की जादूगिरी के चलते ही अनुराग ने शिवराज कावे मीटिंग वाले मुख्यमंत्री बना दिया।

२ एसपीएस परिहार- परिहार साहब भी इकबाल सिंह के ही मेम्बर है। उनका भी वही दायित्व है सीएम को व्यस्त रखना। ये महाशय २४ घंटे सीएम को सिर्फ बिजली के मामलों में उलझाए रखते है। किसानों को भले बिजली के दर्शन न हो रहे हो लेकिन परिहार साहब कागजों और मीटिंग में ऐसे आंकड़े पेश करते है कि लगता है प्रदेश में बिजली का संकट नहीं है।

३विवेक अग्रवाल- अब नए सचिव विवेक अग्रवाल को ही लें, इंदौर में कलेक्टर थे तो एक शराब के ठेकेदार से रिश्वत में एक करोड़ का फ्लैट अपने नाम करवा लिया। भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड इंदौर में तोड़े और अब इकबाल भाई की कृपा से मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंच गए। वह भी ईमानदार और मेहनती अफसर की छवि लेकर। अब ये महाशय भी भाई की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री को लेपटॉप के जाल में उलझाए हुए है। लेपटॉप के रंगारंग में सीएम को सूखी फसल भी हरी-भरी नजर आ रही है। प्रदेश में इस समय फर्टिलाइजर के लिए किसान एक-दूसरे की जान लेने पर आमादा है। ४० हजार मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की मांग के बदले प्रदेश के पास पांच हजार मीट्रिक टन फर्टिलाइजर नहीं है। पहले विवेक ने फर्टिलाइजर इम्पोर्ट करने के सपने दिखाए, फिर कहा कि यहां आते-जाते तक तो फसल पकने का समय आ जाएगा। मंडी बोर्ड संभाल रहे इन महाशय पर ही खेती को लाभ का धंधा बनाने की जिम्मेदारी है।

राज्यमंत्री- ये तो भाई के कैबिनेट मंत्री है। अब बात करते है राज्यमंत्री और स्वतंत्र प्रभार वालों की। स्वतंत्र प्रभार कौन संभाल रहा है। इसमें वे अफस्र है जो मुख्यमंत्री अथ्वा मंत्रियों के इर्दगिर्द रहते है।

१ नीरज वशिष्ठ - इस चेहरे को शायद लोग नहीं जानते हों। ये महोदय इकबाल भाई के सबसे करीबी लोगों में से एक है। नीरज मुख्यमंत्री केक अवसर सचिव है और उनके पीए का काम देखते हे। यानी २४ घंटे सीएम साहब के साथ रहते है। नीरज का काम है कि भाई को सारी खबर देना। सीएम कहां गए, किससे मिले, आदि... आदि। कुल मिलाकर नीरज भाई के निर्देश पर ही सीएम से लोगों की बात करवाता है, मुलाकात करवाता है। वैसे तो नीरज वरिष्ठ को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का माना जाता है, लेकिन वे अब भाई के रैकेट विस्तार हुआ तो नए मंत्रियों के यहां निजी स्टाफ किसी मंत्री से तय नहीं हुआ, बल्कि नीरज शर्मा और भाई की मर्जी से स्टाफ नियुक्त हुआ। सरताज सिंह शिवराज सिंह कैबिनेट में मंत्री तो बनाए गए, लेकिन उनका विशेष सहायक भाई ने तैनात कर दिया। सरताज चाहते थे उनकी पसंद का आदमी नियुक्त हो। इसके लिए उन्होंने नोटशीट भी भेजी, लेकिन हुआ क्या? मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश पर दिलीप कापसे को सरताज का विशेष सहायक नियुक्त कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने बाकायदा इसकी प्रतिलिपी सीएम सेक्रेटरिज को भी दी, जिसमें कहा गया कि उनकी नोट शीट पर कापसे की सेवाएं सरताज सिंह सिंह के यहां सौंपी गई है। अब आप जानिए दिलीप कापसे कौन है। डिप्टी कलेक्टर रैंक के इस अफसर पर गरीबों के अनाज खने पर हरदा थाने में एफआईआर दर्ज है, जांच जारी है, लेकिन इस दागी को नीरज का साथी होने के चलते सरताज के यहां बिठा दिया गया ताकि वन विभाग में भाई की दुकान चलती रहें

२ राकेश श्रीवास्तव-ये रेशम विभाग के अधिकारी है। कुछ समय पहले तक संस्कृति और जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के विशेष सहायक थे। यहां भी ये मंत्री की इच्छा के चलते पदस्थ नहीं किए गए थे, बल्कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने जबरिया उन्हें थोप दिया था। इनकी भी भाई से नजदीकियां चर्चा में है। जब भाई एक जिलें के कलेक्टर थे, तब ये जिला रेशम अधिकारी थे। तब के रिश्ते अब तक चल रहे है। भाई अब इनका जल्दी ही पुनर्वास करवाने वाले है।

३ नरेश पाल- ये महाशय एडीशनल कलेक्टर कटनी के पद पर पदस्थ थे। इससे पहले मंत्रालय में नगरीय प्रशासन विभाग के उपसचिव जैसे मलाईदार पद पर रहे है। ये साहब भी भाई के एकदम करीबी है, सो इस नजदीकी के चलते पाल साहब को स्वतंत्र प्रभार वाले पावरफुल राज्यमंत्री राजेन्द्र शुल्क का विशेष सहायक बना दिया गया। मंत्री की निजी पदस्थापना के लिए सरकार ने बातें तो बड़ी-बड़ी की, लेकिन विभागीय जांच से घिरे होने के बावजूद पाल को मंत्री का विशेष सहायक बना दिया गया। अब पाल के चलते भाई की बिजली और माइनिंग दोनों महकमों में पकड़ बरकरार है।

४ राजेन्द्र सिंह- ये महोदय परिवहन, जेल मंत्री जगदीश देवड़ा के विशेष सहायक है, लेकिन भाई की कृपा से। वैसे तो महोदय कुछ समय पहले ही पदोन्नत होकर राजपत्रित हुए है, लेकिन देवड़ा जी के यहां ये ही सर्वशक्तिमान है। इनके हाल ये है कि मंत्रीजी के निर्देशों का भी राजेंद्र सिंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक भाई क हरी झंडी नहीं मिलती, कोई काम नहीं हो सकता है। परिवहन विभाग में एक साल में जितने लोग डेपुटेशन पर गए, उनका एक पैसा मंत्री को नहीं मिला, क्योंकि राजेंद्र को सारा हिसाब भाई को देना पड़ता है।

५ अजय श्रीवास्तव- ये महोदय बाबूलाल गौर के विशेष सहायक है। कहने को तो गौर साहब कद्दावर नेता है, लेकिन उनकी जान अजय श्रीवास्तव में अटकी है और ये महाशय भाई के खास आदमी है। यूं तो नाम गिनाते-गिनाते हम थक जाएंगे और आप पढ़ते-पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन इकबाल कैबिनेट खत्म नहीं होगी। भाई इतना चतरा है कि शिवराज कैबिनेट के जितने देवड़ा टाइप मंत्री है उनके पास पॉवरफुल विभाग होने का सिर्फ और सिर्फ इतना कारण है कि वे विभाग भाई के डायरेक्टर में चलते हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति डकैतो का अड्डा

खा.नि. परमार- अपनी लूट के लिए सबको खुली छूट

मिलावटी व कम डीजल, पेट्रोल, गैस, राशन का गेहूं, चावल, शक्कर दुकानों से गायब, खुले बाजार में बिक्री

इंदौर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में वर्षों से जमें अजगरो निरीक्षकों से लेकर ४ वर्ष से अधिक समय से जमें खाद्य नियंत्रक डकैत परमार तक सब लूट और वसूली कर चुपचाप तान कर सोते है। कलेक्टर सुलेमान के समय पेट्रोल पंपों पर निरीक्षकों के सामने डीजल, पेट्रोल की जांच कर टैंकों में भरा जाता था। और खाद्य निरीक्षकों के सामने सील लगाई जाती थी। सुलेमान के जाते ही और बाद के जिलाधीशों को चूंकि मोटा महीना मिलने लगा तो सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। इंदौर जिले में चलने वाले १४५ से ज्यादा पेट्रोल, डीजल और गैस पंपों से खाद्य निरीक्षकों को रु. ५ हजार और खाद्य नियंत्रक परमार को रु. १० हजार प्रतिमाह मिल रहा है। इसलिए पेट्रोल, डीजल पंपों में खुले में मिट्टी का तेल, साल्वेंट मिलाकर पेट्रोल बेचा जा रहा हे। वह भी १० प्रतिशत से लेकर ३० प्रतिशत कम बेंचा जा रहा है। अधिकांश पेट्रोल पंप मालिक कर्मचारियों और हॉकरों का वेतन डकार जाता है।साथ रु. १प्रति ली. की अधिक वसूली कर खुले में नाप-तोल में कम नापकर हॉकरों को अपना वेतन वसूलने की खुली छूट देता है। बेशक जहां तक नाप तोल निरीक्षकों का सवाल है, वो खुले में रु. ५००० प्रति माह वसल कर तान कर सोते है। पेट्रोल-डीजल ट्यूब की पारदर्शिता का मामला भी अब फाइलों में जा चुका है। वहीं हाल सीएनजी और एल पीजी गैस पंपों का भी है, जहां उन्हें किलो से तोलकर गैस देनी चाहिए सारे हरामखोर गैस पंप वाले लीटर से गैस बेंच रहे है। वह भी ७००-८०० मि.ली. वह भी वायुमंडलीय गैसों को खीच कर मिला देते है। उपभोक्ता को मात्र ५००-६०० ग्राम भी मुश्किल से असली मिलती है। जिले में ४५० से ज्यादा राशन दुकाने है। ९५ प्रतिशत दुकाने जिनके द्वारा संचालित हो रही है भारी जालसाज है। रु.५००० प्रति माह देकर राशन का गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, शक्कर सप्ताह में ३ दिन दुकान खोलकर बेंचते है बाकी सारा माल काला बाजारी करते हुए दुकानों में खुली बिक्री करवाई जाती है।३ लाख ली. मिट्टी का तेल पर रु.१ प्रति ली. कमीशन परमार लेता है।

यही हाल गैस वितरकों का है ४० से ज्यादा गैस वितरक अपने उपभोक्ताओं को अभी भी ७ दिन से लेकर २ महीने तक में डिलेवरी देते है। जबकि रु. ५०० से रु.६०० में सिलेंडर खुले बाजार में तत्काल उपलब्ध है।हर गैस वितरक रु. २००००/- प्र.मा. परमार को और रु. ५०००/- प्र.मा. निरीक्षक को देता है। इस भ्रष्ट डकैत परमार ने रु. २० लाख के ड्राफ्ट लेकर डकार लिए और मामले में जब विवादों की स्थिति बनी तो हाथ उंचे खड़े कर दिए, यहां बैङ्के निरीक्षकों, सहा.खाद्य नियंत्रकों को ३ वर्ष में हटा दिया जाना चाहिए, परंतु ये हरामखोरों की फौज सबको धन बांट कर लंबे समय से जमी है।

धूर्त परमार प्रति माह रु. ५० लाख से ज्यादा की वसूली कर रहा है। जिसमें रु. १० लाख प्रति माह खा. एवं ना.आ. मंत्री पारस जैन को, रू.१० लाख जिलाधीश को, रु.५ लाख प्रति माह भोपाल मुख्यालय को पहुंचाता है यहीं कारण है, कि सारे लूट और डकैती के बाद भी ४ वर्ष से ज्यादा होने के बाद भी वह यहां जमा है। दूसरी तरफ गांवों से लेकर शहरों तक गरीब, मिट्टी के तेल, गेहूं, चावल, और शक्कर के लिए परेशान होते है। यह हाल इंदौर संभाग के इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर,

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के वासी हैं

आवेदकों, अपालाटंस को मानसिक प्रताडन

म.प्र.सूचना आयोग-जालसाज आयुक्तों का अड्डा

किसी भी आईएएस व धन बांटने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं

मि.अजमेरा हम मंत्री, विधायक, उपर के अपने वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रकारों जैसे १५ कुत्तों को रोटियां डालते है, एक सूचना आयोग जैसे १६ वॉ और सही, उसे भी टुकड़े डालेंगे वो भी हमारे पक्ष में ही फैसला देगा, पीएलई सेवा निवृत्त का अ. जगदीश भाटिया का यह वक्तव्य जो सूचना अधि. अधि.०५ के लागू होने और आयोग के गठन पर उक्त इंजिनियर ने दिया था, एकदम सच था, जिसे यहां बैठे धूर्त जालसाज मु.सू. आयुक्त पीपी तिवारी, सू.आ. आजमगढ़िया जालसाज आयुक्त इकबाल अहमदं, पुलिस विभाग का धूर्त जिसे पत्रकारों ने डकैत संहारक का नाम देकर महान बनाया था, जबकि पुलिस सूत्रों के अनुसार ही इसने कभी कोई डकैत और अपराधी नहीं मारा वरन जिस पुलिस वाले ने डकैत मारा था डले ही उसे दिनेश जुमरान ने मारा बताने के लिए पुलिस वाले को ही निपटा दिया गया, जिसे अपने पूर्व के कुकमों से इतनी दहश रहती है, कि आयोग के कार्यालय में भी आते-आते समय भी रोब झाड़ने और सुरक्षा के लिए अभी भी आदमी रखना पड़ते है।दिनेश जुगरान भी सूचना आयुक्त है। इन तीनों हरामखोरों का इस आयोग में बैठकर शासन की सुख-सुविधाओं का लाभ लेना, सेवानिवृत्ति के बाद भी पूरा वेतन भत्ते, बंगला, लालबत्ती आदि का भरपूर वेतन लेते हुए अपील कर्त्ताओं को ही ये तीनों हरामखोर मानसिक प्रताड़ना देकर अधिकारियों को बचा रहे हैं। ये हरामखोर तीनों आयुक्त, पिछले ५ वर्षो में ५ व्यक्तियों को भी रु. २५०००/- का दंड तो दिया ही नहीं गया साथ ही आवेदक को कानून में व्यवस्था होने पर भी उसे कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं दिलवाई गई,इन भ्रष्ट शूकरों की जालसाजियों में आयुक्तों के साथ वहां पर बैठा स्टॉफ भी महामक्कार, निकंमा और इतना बदत्तमीज है, कि उनसे पूछताछ करेन पर ये अपनीलांटस पर तो एक तरफ फूफकारते है, जबकि दूसरी ओर सरकार अधिकारियों के आगे पीछे घूमते है।फिर पूरा आयोग सरकारी भ्रष्टतंत्र का हिस्सा बन गया है। इसका अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस आयोग प्रदेश के ५० जिलाधीशों और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले ९० से १०५ विभागों में सभी संभागायुक्तों से अपने संभागों की धारा ४ की जिसमें १७ बिंदुओं की जानकारी इंटरनेट साइडों पर डाली जानी चाहिए थी ५ वर्ष बाद भी डलवाने की तो दूर वरन जिन्होंने जिसमें जिलाधीश देवास भी थे इन हरामखोरों न जानकारी डालने के कारण उन्हें पत्र देकर हतोहित ही किया। यदि धारा ४ की जानकार डाल दी जाती तो इन हरामखोरों शतानों की फौज पूछ-परख की समाप्त हो जाती।

इस अधिनियम की जो पारदर्शिता की मंशा थी उस आयोग में घोर भ्रष्ट और निकंमें ही बैठा दिए गए तो कैसे उम्मीद की जा सकती है, कि ये शासन को कहें कि कम से कम चारा ४ जानकारियां डाले,

जिलाधीश जिले का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है, सारि योजनाओं का धन वितरण करने कार्योक पर नियंत्रण रखने, हर सप्ताह सभी अधिकारियों की सभा बुलाने व शासकीय कार्यो को संपन्न करवाने के लिए जिम्मेदार होता है केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उसके जिलाधीश कार्यालय में ही होता है जिसे धारा ४ की जानकारी जिले की साइट पर डालना और समयानुसार अपकृत करना चाहिए। श्री अजमेरा ने देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर आदि जिलों में सूचना के अधिकार में धारा ४ के अंतर्गत जिलाधिशों को हर वर्ष में जानने के लिए पत्र दिए, तो जिलाधीशों ने जानकारी डालना शुरु भी की थी, पत्रों का जवाब संतोषजनक न पाए जाने और जानकारियां न मिलने क दशा में प्रथम व द्वितीय अपीले की इस सूचना आयोग ने श्री अजमेरा की अपीलें खारीज करना दी, इनकी बतमीजीयों का ये उत्कृष्ट नमूना है ये इन पत्रों की प्रतियां संल्गन है।

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
क्र.ए-०४३६/रासूआ/३८-०६/ इंदौर/२००८/३६९३ भोपाल दिनांक ३१/०३/२०१०
प्रति,
श्री अजमेरा एस.पी. कुमार,
२९९, अम्बेडकर नगर,
इंदौर
विषयः- द्वितीय अपील क्रमांक ए-०४३६ श्री अजमेरा एस.पी.कुमार, इंदौर विरुद्ध लोक सूचना अधिकार, कार्यालय कलेक्टर, बुरहानपुर
संदर्भः- १.आपका अपील आवेदन दिनांक ०४/०२/२०१०
आपके द्वारा आयोग को प्रस्तुत द्वितीय अपील क्रमांक ए-०४३६ में आपने लोक सूचना अधिकारी कायग्रलय जिलाध्यक्ष बुरहानपुर को प्रस्तुत आवेदन दिनांक२९.१.०९ को प्रस्तुत कर विभिन्न विभागों से वांछित जानकारी चाही थी।चूंकि इन सभी विभागों में शासन द्वारा पृथक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि प्रथक लोक सूचना अधिकारी के लिए पृथक पृथक आवेदन एवं उसके लिए पृथक प्रथम अपील प्रस्तुत करे। अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय से अनसन्तुष्ट होने पर पृथक आवेदन एवं अपील हेतु पृथक पृथक द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत कर सकते है।

इस परामर्श के साथ ही आपका अपील प्रकरण क्रमांक ए-०४३६ आयोग स्तर पर नस्तिबद्ध किया जाता है।
(प्रकाश खरे),उप सचिव
राज्य सूचना आयोग
मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
क्र.ए-०४३७/रासूआ/३८-०६/ इंदौर/०८/३८१ भोपाल, दिनांक ०१/३/१०
प्रति,
श्री अजमेरा एस.पी. कुमार,
२९९, अम्बेडकर नगर,
इंदौर
विषयः-अपील क्रमांक ए-०४३७ श्री अजमेरा एसप कुमार, इंदौर विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, खंडवा मध्यप्रदेश अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, खंडवा मध्यप्रदेश।
संदर्भः-१. आपका आवेदन दिनांक २०.२.२००९ के संबंध में।
आपके द्वारा आयोग को प्रस्तुत द्वितीय अपील क्रमांक ए-०४३७ के संबंध में अवगत होवें कि आपने दिनांक १६.१२.०८ को लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, खंडवा को आवेदन प्रस्तुत की भिन्न-भिन्न विभागों से संबंधित जानकारी चाही है। कृपया इस संबंध में अवगत होवें कि भिन्न-भिन्न विभागों के संबंध में पृथक-पृथक लोक सूचना अधिकारी पदस्थ है। अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि आप पृथक-पृथक ग्राम विभागों के संबंधित जानकारी चाहने के लिए पृथक-पृथक संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। लोक सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी उपलब्ध न कराने पर पृथक-पृथक लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रथम अपील एवं अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होने पृथक-पृथक द्वितीय अपील आयोग को कर सकते है इस परामर्श के साथ ही आपकी द्वितीय अपील क्र.ए-०४३७ आयोग स्तर पर नस्तीबद्ध की गई है।
(प्रकाश खरे),उप सचिव
राज्य सूचना आयोग

देवास जिलाधीश के विरुद्ध १५/४/०८ को आदेश पारित होने से देवास जिलाधीश ने अधिकांश विभागों की जानकारी न केवल उस पर डाली वरन इस कारण आयोग को देवास के विभागों से अपीले मिलना ही लगभग बंद हो गई, इससे आयोग में बैठा सू.आ. इकबाल अहमद बोखला गया क्योंकि उसकी कमाई पर भी असर पड़ा।

इन निकंमे श्तानों का अपीलायंस को प्रताडित करने का एक अंदाज और भी है, पत्र प्राप्ति के दो तीन महीने बाद भ्रष्ट अधिकारी जो इन्हें पेंट पूजा देता है जिसमें वाणिज्य कर विभाग इन हरामखोरों की महीना मिलता है इसलिए अधिकांश अपीले ये शब्दों के मायाजाल में उलझाकर खारिज कर देते हैं। इसका एक नमूने नीचे देखिए।

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
क्र.ए-०४२४/रासूआ/०७-०२/ इंदौर/०९/३६९५ भोपाल, दिनांक ३१/३/१०
प्रति,
श्री अजमेरा एस.पी. कुमार,
२९९, अम्बेडकर नगर,
इंदौर
विषयः-अपील क्रमांक ए-०४२४ श्री अजमेरा एसप कुमार, इंदौर विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त,वाणिज्य कर, इंदौर।
संदर्भः-१. आपका अपिल आवेदन दिनांक २५.२.२००९ के संबंध में।
आपके अपील आवेदन में निम्नानुसार कमियां हैः-
१.लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक १६.१२.०८ की तीन प्रतियां संलगन नहीं है।
अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि आप उपर्युक्त कमियों की पूर्ति कर आवेदन दिनांक १८.४.२०१० तक भेंजे ताकि आपके प्रकरण में कार्यवाही की जा सके।
(प्रकाश खरे)
उप सचिव,
राज्य सूचना आयोग

उपरोक्त पत्र में जानबूझकर प्रतिवादि का नाम पूरा नहीं लिखा गया अकेले इंदौर में वाणिज्य कर के १० से ज्यादा

(शेष पृष्ठ ५ पर)

पंथपिपलई, धरमपूरी, सांवेर, में बाइपास क्यों?

इंदौर-उज्जैन ४ लेन में भ्रष्टाचार का तांडव

एसडीएम **सांवेर**, उज्जैन, क्षे.त्र.सं.वि.नि. ने मिल करोड़ों डकारे

इंदौर । इंदौर-उज्जैन ४ लेन बीओटी मार्ग निर्माण में चल रहे भ्रष्टाचार से जहा पथपिपलई सांवेर और धरमपूरी में सड़क क्कके किनारे बसे दुकानदार और जनता परेशान हैं। वहीं दूसरी और भूमिअधि ग्रहण

कर नेवाला एसडीएम सांवेर और उज्जैन के साथ महाधूर्त, मक्कार, हरामखोर मप्र सड़क विकास निगम का उज्जैन का क्षेत्रीय प्रबंधक आर के वैद्य जिसने अपनी कमाई के लिए मूल, इंदौर, उज्जैन, सड़क को ही बदल कर इस श्वान ने पथपिपलाई सांवेर और धरमपूरी में लगभग ६.७ किमी मार्ग जो मात्र २ किमी भी नहीं था, नया बनाकर तीनों कस्बों को ही बाईपास कर दिया।

पंथपिपलाई,सांवेर, धरमपूरी में जब पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा स्थानीय भाजपा, कांग्रेसी विधायक तुलसी सिलावट सब ने मिलकर इस भ्रष्टाचार में वर्तमान और भविष्य को ध्यान रखकर एसडीएम पवन जैन सांवेर के साथ मिलकर वारे न्यारे किए है। यह सब षड़यंत्र पंथपिपलई जो उज्जैन जिले में आता है। उज्जैन के एसडीएम के साथ मिलकर किया गया.पंथपिपलाई सांवेर और धरमपूरी में सड़क चौड़ीकरण के लिए सब ने मकानों दुकानो जो अधिग्राहण में आ रही थी पूर्व में निशान लगा दिए गए थे, जैसे ही मुआवजा देने की बात उठी तो, वहां मुआवजा न बांटते हुए सड़क को लगभग ६.७ किमी घुमाव देते हुए बाहर से निकालने का निर्माण लिया गया, इस बात को छिपाकर तीनों ही गांवों के वहां के स्थानीय भाजपाई और कांग्रेसी नेताओं ने जमीनों के दोनों तरफ के सौंदे कर डालें, बेशक इस खेल में धूर्त, भष्टाचार आरके वैद्य और ठैं केदार वराहों की फौज वराह कंस्ट्रक्शन कं. भी शामिल हो गई और मूल डिजाइन को बद कर बाईपास पर दिया गया, आखिर क्यों और कैसे मूल्य डिजाइन बदल गया क्यों बाईपास बनाए जाने तीनों गांवों में, जबकि तीनों ही गांव के लोगों ने जमीने छोड़ने और देने की सहमति दे दी थी, सांवेर में वहां छोड़ने और देने की सहमति दे दी थी, सांवेर में वहां के दुकानदारों ने इस बात के ज्ञापन दिए आंदोलन किए पर शूकर भ्रष्टाचारियों को कमाइ के चलते कानों पर जूं भी नहीं रेंगी।

उज्जैन से २४ किमी सांवेर तक जहां वराहा कंस्ट्रक्शन ४ लेन बना रहा वहां सांवेर खान नदी के बाद से ओमान की कं. गल्फार २४ किमी इंदौर तक बना रही है। ४५ मी चौड़ाई की भूमि का खुले में और गांवों के

बीच से गुजरने वाली सड़क पर ३० मी भूमि चाहिए थे पहले से ही ९ मी साथ में ३ मी और १०-१० दोनों तरफ अर्थात ३२ मी. भूमि उपलब्ध थी और १३ मी. अर्थात ६.५ भी दोनों तरफ भूमि अधिक ही चाहिए था

सूचना के अधिकार में जालसाजी को जानने के लिए इंदौर कलेक्टर को पत्र दिया गया था जिसे सांवेर एसडीएम को स्थानांतरित कर दिया, जानकारी देने की और पैसे भांगने की अपेक्षा सांवेर के एसडीएम ने अपने न्यायालय में उपस्थित होने का ओदश दे दिया ताकि चमकाया और शक्ति संपन्नता दिखाई जा सके। साथ ही मामले को दबाया जा सके इसके विपरीत आवेदक ने अपील लगाने की तैयारी कर ली है। वराहा कंस्ट्रक्शन के केपीसिंग से जब बात की गई तो उसने भी यही बताया कि चारों तरफ भारी भ्रष्टाचार है। इंदौर उज्जैन के इस फोरलेन बीओटी मार्ग ४८ किमी में से ४१ किमी इंदौर संभाग में होने के बाद भी आख्रि उस श्वान भ्रष्ट आर के वैद्य को उज्जैन में क्यों सौंपा गया इसी प्रकार अनेकों इंदौर संभाग की बीओटी की सड़के जो मप्र सड़क विकास निगम के अधिग्रहीत कर रखी है, ये महा जालसाज वैद्य के पास उज्जैन संभाग में क्यों और कैसैं हैं इसके पीछे का राज ये है, कि धूर्त आर के वैद्य जो महा निकम्मा और जालसाज रहा है, ये कैलाश जौशी, भाजपाई नेता के दामाद का भाई है और इंदौर के लो.नि.वि. की धरती पर अवैद्य रुप से काटी गई कालोनी का ही रहवासी है। इस आधार पर बीओटी के सभी कमाई और भ्रष्टाचार

करने योग्य इंदौर संभाग के अनेकों प्रोजेक्ट, एडीबी प्राजेक्ट , एमडीआर, सीआरएफ भी नियम विरुद्ध उसी को दिए गए ताकि वो दोनों हाथों दारों से मिलकर ये इंदौर उज्जैन में ये उपर वर्णित घोटाला तो मात्र जमीनों का खेल है। जबकि इंदौर उज्जैन वैद्य के पास होने के बाद भी उस हरामखोर ने इंदौर उज्जैन जिलों की भूमि से पत्थर गिट्टी, मुरमें की खुदाई के करोड़ों रु. ठेकेदारों से जमा नहीं करवाए बेशक इंदौर के खनिज अधिकारी भ्रष्ट संजय लुनावत ने भी लगभग रु. २ करोड़ गलफर से और रु. १ करोड़ वराहा से उकार लिए है।रावेर

सांवरे, धरमपूरी, की जनता को चाहिए कि वो इस हरामखोर आरके वैद्य को सूचना के अधिकार में मूल डिजाइन कितने लोगों को क्षतिपूर्ति मिली, कितनी मिली, डिजाइन क्यों और कैसे बदला गया की जानकारी एसडीएम सांवेर और उज्जैन से भी मांग सकते है।

बाद में शिकायत लोकायुक्त, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी कर सकते है। पूरे प्रदेश के बीओपी ठेकों में जो २.३५ प्रतिशत कुल ठेके की राशि काव वाणिज्य कर शासन को भी जमा करना चाहिए था आरके वैद्य ने उसे भी उसके ड्रेकों में जमा नहीं करवाया है साथ ही सर्विस टेक्स जो केन्द्र सरकार जाना चाहिए था वह भी जमा नहीं करवाया गया है बाकी भ्रष्टाचार के इस पिटारे की खबरे अगले अंको में,

मल्टी मिडिया मोबाईलों में, नीली फिल्मों का अंबार (पृष्ठ ८ का शेष)

भारत में सूचना प्राद्योगिकी या इंफारमेंशन टेक्नालॉजी एक्ट २००० में इस प्रकार से चित्रांकन करना विडियों बनाना मोबाइलों में विडियों रखना विडियों देखना, दिखाना, एसएस से प्राप्त करना भेजना, ईमेल ब्ल्यू टूथ, वायरलेस, इंटरनेट से चुराना भेजना, व्यवसाय करने पर न केवल प्रतिबंध है वरन पकड़े जाने पर ७ वर्ष की सजा तक का प्रावधान है। साथ ही नगद दंड भी दिया जा सकता है। शासन के सभी निजी और शासकीय शिक्षण संस्थाओं में इस आशय के न केवल नोटिस भेज कर नोटिस बोर्ड पर लगवाए जाने चाहिए जिसमें सजा और आर्थिक दंड दोनों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए । साथ ही शासन को पुलिस विभाग को ये लिखकर और निर्देश भी भिजवाए कि वो स्कूलों, कालेजों में विद्यार्थियों के मोबाइल फोनों की अचानक छापे मारकर जांच करे जिससे विद्यार्थियों में न केवल भय व्याप्त हो, स्वयं विद्यार्थी मल्टी मिडिया मोबाइल स्कूलों और कालेजों में रखना बंद कर दें। सभी देशों के प्रशासन और स्कूली शिक्षा विभाग पहले नोटिस जारी करे बाद में एक माह बाद ही चाहे जब स्कूल में प्रवेश के समय ही मोबाइलों की जांच करे, और मोबाइल जप्त कर लें, न मानने पर तीन बार नोटिस देकर पहले एक माह के लिए, फिर ३ माह के लिए और पूरे वर्ष भर के लिए स्कूल, कालेज विश्वविद्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा जिससे स्वयं विद्यार्थी और उसके माता-पिता न केवल सचेत हो जाए वरन् स्वयं ही मल्टी मिडिया मोबाइल न दे। इससे युवा विद्यार्थी न केवल इस गंदी मानसिकता में उलझने से बचेंगे वरन् पढ़ाई पर ध्यान भी केन्द्रित कर सकेंगे।

नारी का धरती पर मां से बड़ा सम्मान क्या हो सकता है?

महिला आरक्षण या शोषण

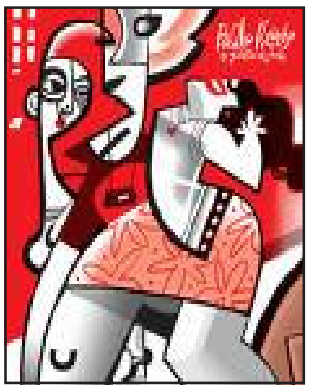

भारत की १२०करोड़ की आबादी और राष्ट्र को चलाने वाली लोक सभा में महिलाओं के ३३ प्रतिशत आरक्षण पर पिछले सग में भारी गहमा गहमी रही, क्या सचमुच महिला आरक्षण है या महिलाओं का चहुंदिशि शोषण बिल है,

पृथ्वी पर नारी का सबसे बड़ा सम्मान हे उसका मां होना, भारत में मां की महिमा में पुराणों, शाखों और वेदों में ही वृतांत दिए गए है।वह केवल जन्मदागी ही नहीं वरन मानव की शिशु काल से लेकर जीवन पर्यन्त संभालती है। साथ ही वह परिवार समाज और राष्ट्र के भावी निमार्ण की आधार शिला भी रखती है। वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी में बढ़ती संस्कार ही नता उच्च शृंखलता के लिए भी नारी ही जिम्मेदार है उसका स्वाभाविक सा कारण है कि अब कमाने भी जाती है। बच्चों के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की न केवल भरण पोषण, देखभाल करने से लेकर भविष्य के लिए शिक्षा दीशा की देखरेख भी करना उसकी जिम्मेदार में आता है। यदि भारत एक संस्कार और परंपराओं का राष्ट्र था तो केवल उसकी मां पत्नि,दादी, नानी, काकी,बहु की पारिवारिक भूमिका को पूर्ण समर्पण के साथ निभाना ही था जब वह ही घर पर बाजार की व्यावसायिकता और धन के प्रति मोह तो बढ़ेगा ही वरन घर की, परिवार की देखरेख करने में न तो समय के पाएगी, न ही भलीभांति वह बच्चों की देखरेख शिक्षा, दीक्षा, समुचित विकास की ओर ध्यान दे पाएगी, समय के साथ शिशु से बच्चे, बच्चों से युग होती पीढ़ी को मां के समयाभाव कान केवल देश जीवन भर चुमेगा, न बच्चों में मां के प्रति और न मां में बच्चों के प्रति वह स्नेह, समर्पण और सम्मान होता है। अधिकांश कामकाजी महिलाए, जो एक बार बाजार में कामकाज, नौकर आदि के लिए आने जाने लगती है। स्वाभाविक है पैसे की चमक-चमक और लालच में तन-मन का सुख पाने के अपना मानसिक और शारीरिक शोषण की शिकार भी होती है। पहले वो शिकार होती है, फिर शिकार होते-होते तो स्वयं शिकारी बन जाती है, इस भाग दौड़ में पति, बच्चों परिवार पीछे छूटने लगते हैं। परंपराओं, संस्कारों की बात तो निरर्थक और पैसा मापदंड बन जाता है।दूसरी ओर पुरुष चाहे पति हो, बेटा हो, देवर, भाइ-भाभी, मां-बाप उसकी कमाई के चलते धीरे संबंधों की खातिर उस पर आर्थिक बोझ भी बनने लगते है।बात यहीं तक नहीं थमती स्वयं मां-बाप भाई,बहिन तक कुवारी लड़कियों की शादी तक होने देते, क्योंकि एक तरफ वह दूध देने वी गाय और दूसरी मा-बाप, भाई-बहिन, भाभीयों आदि के लिए काम करने वाली आया की भी भूमिका अदा करती है।अर्थात् कमाई के चलते उसके अपने ही उसकी जिंदगी के प्राकृतिक सुखों से वंचित कर ऐसी महिलाओं का चहुं दिशि शोषण करते है । यदि महिला शादी शुदा होती है, तो फिर सबसे बड़ा शोषण कर उसका पति ही हो जाता है। गांवों में ५० प्रतिशत

नारी को घर से बाहर निकाल, बाजारु बना, परिवार समाज, राष्ट्र करेंगे बर्बाद

सरपंचों अध्यक्षों, मंत्री, पंचायत के महिला पार्षदों में पतियों द्वारा पत्नि के पद का दुरुपयोग उनक आड़ में वसूली, भ्रष्टाचार,रोब झाड़ना, पत्नि के साथ कार्यालय पड़ोस में ही कुर्सी लगाकर सलाह देने की आड़ में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का कार्य न केवल देवास की जिला पंचायत अध्यक्ष कमला गोस्वामी के साथ ही पूरे राष्ट्र में भी हो रहा है। दूसरी ओर जो महिलाए घर से बाहर निकलकर कार्य या राजनीति के सिलसिले में बाहर निकलती है। स्वाभाविक है हर दिन अनेकों लोगों, कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलते-मिलते मन से तन के समर्पण तक पहुंचकर अनेकों के साथ हमविस्तर होती है, धीरे-धीरे यह सिलसिला घर तक पहुंचकर घर,परिवार, समाज और राष्ट्र की , कारण बनने लगता है। यहि कारण है कि वर्तमान में विदेशों की तरह हमारे राष्ट्र में भी तलाकों की संख्या में पूर्व के वर्षो की तुलना में गुणात्मक वृद्धि हो रही है। जो स्पष्ट करती है, कि तुलना में गुणात्मक वृद्धि हो रही है। जो स्पष्ट करती है, कि महिलाओं को बाजारु बनाने से किस प्रकार घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की बर्बादी हो रही है। जिस अमेरिकी इशारे पर सन्१९६० के बाद जितने भी कानून बनाए गए सब उसके हितों के साधन के लिए ही बनाए भारत की बर्बादी के लिए, उसने भारत के विकास की राहों में अपने हित पहले साधे, चाहे के परमाणु समझौता हो या महिला आरक्षण विधेयक, भारत की घर, परिवार, समाज और राष्ट्र को बर्बाद करने के महिलाओं को घर से बाहर निकालकर बाजारू बनाने पर तुला स्वयं अमेरिका बताए कि उसके यहां ऐसा कौन सा कानून है, जिसमे जातिवाद, महिलाओं का ही रहे जान केवल अमेरिकी सीने में नहीं है, वरन अमेरिकी की स्वयं की अन्य दूसरी स्टेटस में भी कोई ऐसा कानून नहीं है। यही नहीं परे युरोप चाहे ब्रिटेन हो इटली, जमीनी, फ्रांस कोई सा भी राष्ट्र में राष्ट्र की संसार में कोई ऐसा कानून नहीं है कि निश्चित प्रतिशाह में महिलाओं ही रहेंगी। (शेष पृष्ठ ३ पर)

स्कूलों में १२ वीं तक, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए

मल्टी मिडिया मोबाईलों में, नीली फिल्मों का अंबार

आई टी एक्ट 2000 में हो सकती है, 7 वर्ष की सजा

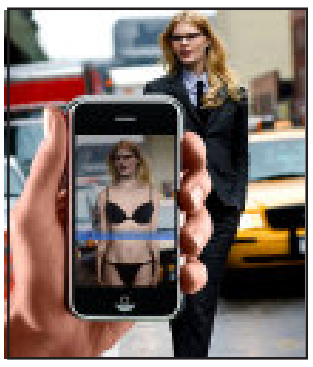

पुरे राष्ट्र में पचासों कंपनियों के मल्टी मिडिया मोबाईल की भरमार है, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग १२ वर्ष के विद्यार्थियों से ३० वर्ष तक के युवा सबसे ज्यादा कर रहे है। जिसमें एम पी ३ गानों से लेकर ४ से १० जीबी के भंडार में २५०० गानों से लेकर १००-२०० नीली यौनाचार की फिल्में व विडियों भरे होते है। साथ ही उसमें कैमरा और १ से ३० मिनिट तक की विडियों फिल्मों का निर्माण, शूट या रिकार्डिंग की जा सकती है। इस सुविधा निर्माण, शूट या रिकार्डिंग की जा सकती है। इस सुविधा के दुष्परिणामों के बारे में हर दिन विश्व के कोने-कोने से अपनी ही सहपाङ्गी से दोस्ती आर उसको साथ सह चर्य के साथ उसकी नगन्ता, योनाचार का खुला प्रदर्शन पूरी दुनिया की इंटरनेट पर चलनेवाली हजारों साइटों पर प्रदर्शन खुले में किया जा रहा है। कभी चोरी छिपे, अधिकांश मामलों से स्वयं लड़कियों ने अपनी नगन्ता के प्रदर्शन और जो यौताचार को ही अपनी कमाई और मौजमस्ती का साधन स्वयं ही लोड कर इंटरनेट साइटों पर अपने मोबाइल नंबरों के साथ प्रदर्शन कर रही है। यह कार्य अब ७ वी,८वी के विद्यार्थियों सेलेकर उच्च डिग्री पाङ्गचक्रम करने वाले युवाओं में कुछ ही वर्षो में तेजी से फैल चुका है। वैश्विक स्तर पर दोस्ती करने वाली, हजारों साइटें इससे अरबों रु. का व्यवसाय कर रही है। भारत दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, कोलकत्ता के साथ सभी महानगरों से लेकर छोटे-छोटे गांवों तक यह संस्कृति पैर पसार चुकीहै। जिससे सबसे ज्यादा शिक्षक परेशान हो रहे

है। इसके दूसरी ओर शातिर धूर्त, स्कूल संचालकों प्राचार्यों से लेकर शिक्षक शिक्षिकाएं तक दूसरा भरपूर फायदा उङ्गाकर युवा पीढ़ी को यौनाचार के लिए विवश करने से लेकर पैसों तक के लिए ब्लेकमेल तक किया जा रहा है। इंदौर में कुछ वर्षो पूर्व एक कुख्यात संचालक को इस बुक में कांड में पकड़ा भी गया थ जो हिन्दु लड़कियों को जो उसके स्कूल में पड़ती थी, वो जालसाज ऐसी हर सुंदर शिक्षिकाओं और लड़कियों की नीली फिल्में बनाकर उन्हें न केवल ब्लेक मेल करता था वरन् स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर अपने मित्रों के पास पहुंचाने का कार्य भी करना था बेशक अधिकांश शातिर स्कूल संचालकों शिक्षकों और शिक्षिकाओं के साथ ही विद्यार्थियों के लिए मल्टी मिडिया मोबाईलों से यह काम अब और आसान हो गया है।इसके विपरीत यह शिकायत भी मप्र के देवास जिले के एक दूरस्थ गांव अजमान में, एक सीधे सादे शिक्षक ने ही की थी, जब इस बात को समय माया के प्रबंध संपादक ने इंटरनेट के टवीटर की साईट पर डाला कि १२ वीं कथा तक स्कूलों में मल्टी मिडिया मोबाइल बंद किए जाए तो युरोप में इस साइट के इस वाक्य पर मोबाइल पर १७३९ लोगों ने २४ घंटों में पढ़ा और १६७६ लोगों जिसमें अधिकांश विद्यार्थी ही थे, सहमति जताई, अर्थात् इस गंदगी से स्वयं व्यक्तित्व स्तर पर विद्यार्थी भी न केवल परेशान हो चुके है वरन् उनकी वास्तविकता में पढ़ाई बाधित होकर मानसिक संताप का कारण बन रही है। तो दूसरी तरफ हल्के मोबाइल रखना, उनमें गरीब होने या असक्षमता की तरफ इंगित करता है, अगर शासन की स्कूलों में प्रतिबंधित कर देगा तो अपने आप ही मल्टी मिडिया मोबाइल से मुक्ति मिल जाएगी और पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही विद्यार्थी अपने ही सहपढियों से ब्लेक मेल होने से स्व मेव ही बच जाएंगे।

(शेष पृष्ठ ७ पर)

ओबामा, बुश की गुंडागर्दी की राह पर

अमेरिकी गुंडे का ईरान में आतंक

ईरानी तेल और धरती चाहिए, दक्षिण एशिया में कहर बरपाने

अमेरिका ईरान पर न केपल तेल, वरन् अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए हिन्द महासागर से ईरान धरती से अपनी सेवा हथियार मिसाइल, गोला बारूद ले जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए येन-क्रेन प्रकरेण कब्जा करने के प्रयास के पिछले ७-८ वर्षो से षड़यंत्रों के अंजाम दे रहा है, कभी स्वयं ही उसकी जल सीमा में अपने सैम्य अभ्यास के लिए घमक जाता है।

१ यादि अफगानिस्तान तक उसकी मारी से न्यसामग्री अर्गिलरी, पर माणु मिसाइलें, भारी टैंकों आदि आने जाने क आसान व्यवस्था हो जाए, तो ये विश्व का गुंडा आसानी से इसके ऐतिहासिक शत्रुओं, रूस, चीन, भारत पर आक्रमण कर उनके प्राकृतिक संपदाओं पर कब्जा कर विश्व को हांकने के साथ धरती की भी आवश्यकता है। ईरान में राष्ट्रपति अहमदीनेजाक के चुने जाने से अमेरिकी मंसूको पर पानी फिर गया, इसलिए राष्टपति के चुनाव में धांधली का आरोप लगा कर गृह युक्त भड़कने का पूरा षड़यंत्र रच रहा है, आखिर तो कौन है, जो दूसरे राष्ट की संप्रभुता में हस्तक्षेप कर रहा है।

भारत के सत्राधीश अमेरिकी सत्राधीशों के गुलाम है जब तक ईरान सुरक्षित है, तभी तक दक्षिण एशिया में जो बचीकुची शांति है कायम है। जिसदिन उसकी पूर्ण क्षमता अफगानिस्तान तक पहुंची पाकिस्तान को पीछे से सहयोग कर भारत से भी प्रत्येक्ष राष्ट करेगी, अमेरिका या पाकिस्तान की आईएसआई के माध्यम से स्वयं ही परमाणु हथियार आतंकवादियों को युद्ध कर उसे अपने हथियार बेचना है। षड़यंत्र की असफलता का बदला ईरान को ग्रहयुद्ध में झोंककर उसे आंतारिक रूप से कमजोर कर मौका मिलते ही आक्रमण कर दे ये धूर्त, ईरान में अहमदीनेजार के पुनः राष्ट्रपति बन जाने से अमेरिकी जुंडाग दींव दादागिरी को गहरा आघात पहुंचा है, पिछले लगभग एक दशक से ईरान को चमकाने, डराने, ईराक और अफगानिस्तान की तरह कब्जा करने के मंसूबो पर अहमेदीनेजाद सिरे से न

सरदार पाक हमारा द. एशिया में श्रेष्ठ साझेदार है। मैं प्रयास करूंगा कि मेरा पाक और तुम्हारा संतुलन बना रहे ताकि मेरे हथियार विक्रेताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवसाय चलता रहे।

सेलफोन कंपनियों की सफेद पोश डकैती-

नंबर पोर्टबिलीटी का नया अंदाज

मफ्त कहेंगे और लूटेंगे, उपभोक्ता मुफ्त के चक्कर में बात करेगा

नई दिल्ली-दूर संसार नियामक आयोग करबों रूपए उकार कर सेलफोन कं. के इशोर पर नंबर पोर्टबिलीअी का जो ढ़ांचा तैयार कर रही है और तीन माह बाद लागू करने जा रही है, उसके पीछे सेलफोन कं. के सफेद पोश डकैतों, जिसमें टाटा, रिलांयस, आइडिया, भारती, वोडाफोन, बी.एस.एन.एल व अन्य सभी सेल कं. शामिल है। उपभोक्ता को लूटने के नए शड़यंत्रों की कूट रचनाकर मफ्त सेवा के बहाने लूट और वसूली के साथ देश की, उपभोक्ता की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है।

अभी सभी कंपनियां उपभोक्ताओं को शड़यंत्र से फंसा कर की उनके हीमोवाइलों पर अंतर नगरीय, प्रांतिय और राष्टीय द्वय स्तर पर मुफ्त सेवा मिलेगी, इस चक्कर में मोबाइल उपभोक्ता अपने संपर्क के लिए अलग-अलग कंपनियों के मुफ्त के चक्कर दो, तीन,चार मोबाइल तक रख रहा है, ताकि वह एक ही कंपनियों के मोबाइल पर मुफ्त सेवाओं का लाभ उङ्गा सके, इसके विपरित जैसे ही नंबर पोटबिलीटी सुविध की घोषणा हुई और यह शड़यंत्र स्थायी रूप से स्वीकारा गया, तो भी उपभोक्ताओं से मुफ्त कहा जाएगा और पूरी वसूली की जाएगी क्योंकि नंबर फिर किसी का लगाने पर कंपनियां मुफ्त की सेवाओं के नाम पर वसूली तो करेंगी साथ ही उपभोक्ता जब पूछताछ करेगा, तो कहेंगी की नंबर हमारी कंपनी का हीथ अन्य दुसरी सेल कं.में चला गया है, इसलिए उस पर तो शुल्क लगेगा, तीसरा इसके बहाने बीएसएनए जो मूल सक्त सेवा प्रदाता है, उसके टावरों को जो कि संख्या में और सेवा में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। निजीकंपनियां उन टावरों का भ पोर्टबिलिटी की आड़ में खुलकर उपयोग करेंगी बदले बदले में बीएसएनएल के अधिकारियोंको जो कि सच्चाई में दूरसंचार निगम के अधिकारी है दोनों हाथ मासिक अवैघ वसूली कर अन्य सभी कंपनियों को अपने टावरों से सेवा दे सकेंगे। जिसक व्यय/शुल भी उपभोक्ताओं से ही वसूला जाएगा, अर्थात उसक आड़ में भी जेब कटेगी उपभोक्ताओं की ही और किसी ने इस पर वाद भी दायर किया या उपभोक्ता न्यायालय में भी गया हो सभी कंपनियां एक दूसरे पर मामला डालकर न्यायालयों को भी भ्रमित कर उलझाकर बच निकलेंगी।

इस सबके विपरीत इससे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी,

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.
भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2530859 मो. 93007-55803